www.ghoonghatkibagawat www.ghoonghatkibagawat

ghoonghatkibagawat37@gmail.com

UP/HIN/1999/1282

घूँघट की बगावत

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

वर्ष : 24 अंक : 05 गोरखपुर, 28 जुलाई 2024 रविवार पृष्ठ : 8 मूल्य : 2

माझी लड़की बहिन योजना की घोषणा

महाराष्ट्र जैसे समृद्ध राज्य के लिए खर्च... अजीत पवार

मुंबई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने शनिवार को कहा कि राज्य मंत्रिमंडल के अलावा वित्त और योजना के साथ-साथ अन्य संबंधित विभागों की मंजूरी के बाद मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना की घोषणा की गई। योजना के कारण सरकारी खजाने पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को लेकर विपक्ष की आलोचना के बीच, जिसके तहत महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता मिलेगी, पवार ने कहा कि महाराष्ट्र जैसे समृद्ध राज्य के लिए यह खर्च वहन करना संभव है। एक बयान में एकनाथ शिंदे सरकार में वित्त और योजना विभाग संभालने वाले पवार ने कहा कि उन्होंने "वित्त और योजना, सभी संबंधित पक्षों की मंजूरी" के बाद वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के अनुपूरक बजट में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना पेश की। पवार ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में योजना के लिए आवश्यक रुपए 35 हजार करोड़ की पूरी राशि इस वर्ष के बजट में ही प्रदान की गई है। इसलिए, यह सवाल ही नहीं उठता कि योजना के लिए पैसा कहाँ से आएगा। यह वित्तीय रूप से संभव है महाराष्ट्र जैसे समृद्ध राज्य को इतनी राशि खर्च करनी होगी। राकांपा नेता ने कहा कि राज्य सरकार यह राशि माताओं-बहनों-बेटियों की आर्थिक स्वतंत्रता, स्वावलंबन, पोषण और सर्वांगीण सशक्तिकरण, मान-सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने के लिए खर्च करने को तैयार है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि इस राज्य में किसी के पास इस योजना का विरोध करने का कोई कारण नहीं है। योजना के लिए वित्त विभाग के विरोध की रिपोर्ट, जो कुछ मीडिया आउटलेट्स में प्रकाशित हुई हैं, काल्पनिक, तथ्यों के साथ असंगत और राजनीति से प्रेरित हैं। पार्टी नेता ने कहा. मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना के तहत, 21-65 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को जिनकी पारिवारिक आय रुपए 2.5 लाख से कम है, उन्हें रुपए 1,500 प्रति माह दिए जाएंगे। बजट में योजना की घोषणा करते हुए, पवार ने कहा था कि इस योजना पर 46,हजार करोड़ रुपये का वार्षिक खर्च आएगा।

बारिश ने मचाया कहर, रेड अलर्ट

पुणे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है, जिसके बाद कई एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। गुरुवार को अपने बुलेटिन में, मौसम विभाग ने कहा कि 26 और 27 जुलाई को मध्य महाराष्ट्र, कोंकण क्षेत्र और राज्य के अन्य इलाकों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। मुंबई और पुणे में भी स्थिति गंभीर बनी हुई है, क्योंकि मौसम विभाग ने भारी बारिश की भविष्यवाणी करते हुए 'रेड अलर्ट' जारी किया है। हालांकि, बृहन्मुंबई नगर निगम ने कहा कि शुक्रवार को सभी स्कूल और कॉलेज खुले रहेंगे।

मुंबई में मौसम और बारिश फिलहाल सामान्य है, जिससे महानगर में जनजीवन सुचारू रूप से चल रहा है। इसके परिणामस्वरूप, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) क्षेत्र के सभी स्कूल और कॉलेज कल, शुक्रवार, 26 जुलाई 2024 को नियमित रूप से खुले रहेंगे। अभिभावकों से विनम्र अनुरोध है कि वे स्कूल और कॉलेज की छुट्टियों के बारे में किसी भी अन्य जानकारी या अफवाहों पर विश्वास न करें और केवल बृहन्मुंबई नगर निगम की आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। नागरिक प्रशासन नागरिकों से अधिक जानकारी के लिए संबंधित स्कूलों और कॉलेजों के प्रबंधन के संपर्क में रहने का आग्रह करता है, नागरिक निकाय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा। इससे पहले गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा के लिए उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के साथ गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक के बाद, मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत कार्यों में तेजी लाने और मदद पहुंचाने के लिए पूरे राज्य में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ इकाइयों, सेना, नौसेना, पुलिस, अग्निशमन दल और डॉक्टरों की टीमों को तैनात किया गया है।

शिंदे ने कहा, मैंने पुणे से संबंधित सेना और नौसेना के अधिकारियों से बात की है। मैंने बाढ़ के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर तैनात करने को कहा है। शिंदे ने कहा,एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, नौसेना, पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य प्रणाली की इकाइयों को एक-दूसरे के साथ समन्वय करने और मदद करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि इन एजेंसियों को एक टीम के रूप में काम करने और बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करने, उन्हें भोजन के पैकेट उपलब्ध कराने, दवाइयों और पानी की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ, सेना और नौसेना की मदद लेने के निर्देश दिए गए हैं। पुणे, मावल और मुलशी में बांध क्षेत्र में भारी बारिश हुई है, इसलिए पुणे प्रभावित हुआ है। मुंबई शहर और उपनगरों में भी भारी बारिश हो रही है। मुंबई में किसी भी आपदा से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और मैं पुणे, रायगढ़, मुंबई कलेक्टरों और नगर आयुक्तों के संपर्क में हूं।

एस-400 का विकास इतिहास

एस-400 सिस्टम को विकसित करने का काम 1980 के दशक के अंत में शीत युद्ध के अंतिम वर्षों के दौरान शुरू हुआ था। रूसी वायु सेना ने पहली बार जनवरी 1993 में स-400 प्रणाली की घोषणा की थी। पहला सफल परीक्षण 12 फरवरी 1999 को किया गया था और इसे 2001 में रूसी सेना में तैनात करने के लिए निर्धारित किया गया था। अल्माज-एंटे के डॉ. अलेक्जेंडर लेमन्स्की स-400 परियोजना के मुख्य अभियंता थे। हालांकि, 2003 में यह स्पष्ट हो गया कि मिसाइल प्रणाली तैनाती के लिए तैयार नहीं थी और परिणामस्वरूप नई डिजाइन प्रणाली लागू की गई। परियोजना के पूरा होने की घोषणा फरवरी 2004 में की गई और अप्रैल में उन्नत 48एन6डीएम मिसाइल के परीक्षण में एक बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक रोका गया। 2007 में, सिस्टम को सेवा के लिए मंजूरी दे दी गई और तब से इसका उपयोग किया जा रहा है।

स-400 के घटक क्या काम करते हैं?

स-400 मिसाइल सिस्टम स्वायत्त पहचान और लक्ष्यीकरण प्रणालियों के साथ एक एकीकृत मल्टीफंक्शन रडार के साथ आता है। इसमें एंटी-एयर मिसाइल लांचर और कमांड और कंट्रोल मिसाइल भी शामिल हैं। यह एक स्तरित रक्षा के लिए निम्नलिखित मिसाइलों को फायर करने में सक्षम है।

48एन6डीएम 250 किमी तक हवाई लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम

40एन6: 400 किमी की दूरी तक पहुंचने का दावा किया जाता है, यह लंबी दूरी पर हवाई लक्ष्यों को रोकने के लिए सक्रिय रडार होमिंग का उपयोग करता है।

9एम96ई- यह मिसाइल लड़ाकू विमानों जैसे गतिशील लक्ष्यों पर बहुत सटीकता से हमला कर सकती है।

9एम96ई5: 9एम96ईका एक मध्यम दूरी का एयर-टू-एयर मिसाइल संस्करण, यह सीधे प्रभाव के लिए उतारा जाता है। 9एम96 मिसाइल के दोनों संस्करण 102 किमी की दूरी तय करते हैं।

यह प्रणाली एसए-12, एसए-23 और एस-300 जैसी अन्य रक्षा प्रणालियों के साथ डेटा का आदान-प्रदान करने में भी सक्षम है। रडार 600 किमी की दूरी के भीतर विमान, रोटरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइलों, निर्देशित मिसाइलों, ड्रोन और बैलिस्टिक रॉकेट का पता लगा सकता है और उन्हें ट्रैक कर सकता है। यह एक साथ 300 लक्ष्यों पर नजर रख सकता है।

भारतीय वायुसेना के अभ्यास में एस-400 वायु रक्षा प्रणाली ने लगभग पूरे 'दुश्मन' को मार गिराया

सुदर्शन एस-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली को एक अभ्यास में बड़ी सफलता मिली, जिसमें इसने 'दुश्मन' लड़ाकू विमान पैकेज के 80 प्रतिशत को 'मार गिराया' जबकि अन्य को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जिससे उनके मिशन रद्द हो गए। रक्षा सूत्रों ने एएनआई को बताया कि यह अभ्यास भारतीय वायुसेना द्वारा एक थिएटर में किया गया, जहां बल ने लंबी दूरी की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के अपने एक स्क्वाड्रन को तैनात किया था।

उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना द्वारा वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के बल में पूर्ण एकीकरण को प्रदर्शित करने के लिए यह अभ्यास किया गया था। अभ्यास के दौरान, असली लड़ाकू विमान एस-400 हथियार प्रणाली की क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए उड़ान भर रहे थे, जिसे अब भारतीय वायुसेना द्वारा भगवान कृष्ण के शक्तिशाली सुदर्शन चक्र के नाम पर सुदर्शन कहा जाता है। सुदर्शन, नकली कार्रवाई में 'लॉकिंग और लक्ष्यीकरण' करके, 'दुश्मन' के आक्रामक पैकेज के 80 प्रतिशत को 'मार गिरा' सकता है। शेष बचे विमानों ने अपना मिशन रद्द कर दिया, जिसका उद्देश्य भारतीय क्षेत्र में अपने लक्ष्यों पर 'हमला' करना था और उन्हें वायु रक्षा प्रणाली द्वारा रोक दिया गया।

भारतीय वायु सेना ने अब इस प्रणाली को पूरी तरह से एकीकृत कर लिया है, जिसके तीन स्क्वाड्रन पहले ही शामिल किए जा चुके हैं और 2026 में दो और की आपूर्ति होने की उम्मीद है। भारतीय पक्ष ने अनुरोध किया है कि रूस सिस्टम की डिलीवरी में तेजी लाए।

रूस की एक उच्च स्तरीय यात्रा के दौरान भारतीय पक्ष ने रूसी पक्ष से सिस्टम की डिलीवरी का भी अनुरोध किया। भारत और रूस ने स-400 के पांच स्क्वाड्रन के लिए 35,हजार करोड़ रुपए से अधिक के सौदे पर हस्ताक्षर किए। भारतीय वायु सेना, जिसने हाल ही में स्वदेशी टीएफ़एवॉट और आकाश मिसाइल सिस्टम के साथ-साथ इजराइली स्पाइडर क्विक रिएक्शन सरफेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम प्राप्त किया है, का मानना है कि स-400 इसके लिए गेम चेंजर साबित होगा। भारतीय वायु सेना अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में प्रोजेक्ट कुशा के तहत भारतीय लॉन्ग रेंज सरफेस एयर मिसाइल सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी। यह विकास परियोजना को सुरक्षा पर कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद हुआ।

भारतीय वायु सेना, जिसने हाल ही में स्वदेशी एमआर-एसएएम और आकाश मिसाइल सिस्टम के साथ-साथ इजरायली स्पाइडर क्विक रिएक्शन सरफेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम प्राप्त किया है, का मानना है कि एस-400 उसके लिए गेम चेंजर साबित होगा। भारतीय वायु सेना ने हाल के वर्षों में अपनी वायु रक्षा क्षमताओं में उल्लेखनीय सुधार किया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार चीनी सेना द्वारा बड़े पैमाने पर वायु रक्षा प्रणालियों को तैनात किया गया है, जबकि भारत ने भी वहां बड़े पैमाने पर अपनी खुद की प्रणालियों को तैनात किया है। एस-400 ट्रायम्फ (रूसी में ट्रायम्फ) मिसाइल सिस्टम रूस के अल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित एक एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। यह 2007 से रूसी सशस्त्र बलों के साथ-साथ अन्य अंतरराष्ट्रीय ऑपरेटरों द्वारा उपयोग में है। एस-400 मिसाइल सिस्टम लगातार खबरों में रहे हैं क्योंकि भारत ने रूस से उन्हें खरीदने की योजना बनाई है, लेकिन इस तरह के कदम ने संयुक्त राज्य अमेरिका से बहुत आपत्ति जताई है, अगर पूरी तरह से निंदा नहीं की है।

कोटा मुद्दे पर जोरदार हंगामा, विपक्ष ने किया विरोध प्रदर्शन

पटना। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन हंगामेदार दृश्य देखने को मिला। विपक्ष ने केंद्र द्वारा राज्य को विशेष दर्जा देने से इनकार करने सहित कई मुद्दों पर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर निशाना साधा। विशेष दर्जे के अलावा, राज्य के संशोधित आरक्षण कानूनों पर एक निजी विधेयक पर मतदान कराने की उनकी मांग खारिज होने के बाद विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी राजद और कांग्रेस विधायकों ने राजद एमएलसी सुनील सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी आलोचना की, जिसके कारण उन्हें राज्य विधान परिषद से हटा दिया गया और राजद विधायक रेखा देवी के बारे में नीतीश कुमार की हालिया टिप्पणी की भी आलोचना की गई। अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने वाले सुनील सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दोषी ठहराया। सिंह ने आरोप लगाया कि अगर जांच कराई गई तो कुमार सबसे भ्रष्ट समाजवादी के रूप में बेनकाब हो जाएंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें कई बार धमकी दी है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई व्यक्तिगत प्रतिशोध से प्रेरित है। देवी ने दावा किया कि भाजपा-जदयू शासन के तहत भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय शुरू हो गया है।

पीएम मोदी का दावा है कि 70 वर्षों में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं हुआ है। क्या इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अकेले ही देश को बदल दिया है, जबकि उनके पूर्ववर्तियों ने कुछ नहीं किया? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राबड़ी देवी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वह मुख्यमंत्री थीं, एक पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी थीं और एक पूर्व उपमुख्यमंत्री की मां थीं। अगर सचमुच लोकतंत्र खत्म हो गया होता तो उन्हें आजादी नहीं होती।

अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने वाले सुनील सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दोषी ठहराया। सिंह ने आरोप लगाया कि अगर जांच कराई गई तो कुमार सबसे भ्रष्ट समाजवादी के रूप में बेनकाब हो जाएंगे।

पत्नी की आत्महत्या प्रकरण :

डिप्टी सीएमओ को सात साल की सजा

बांदा। जिले की एक विशेष अदालत ने पत्नी के खुदकुशी करने के मामले में ललितपुर जिले में तैनात उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (डिप्टी सीएमओ) को बृहस्पतिवार को सात साल कैद और सात हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजक ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मामले में तीस साल बाद फैसला आया है। विशेष अदालत के अभियोजक मनोज कुमार दीक्षित ने बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद त्वरित न्यायालय की विशेष न्यायाधीश पल्लवी प्रकाश ने यह फैसला सुनाया। उन्होंने बताया कि ललितपुर में तैनात उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉअशोक कुमार कथेरिया की पत्नी शकुन ने 20 मार्च 1996 को बबेरू कस्बे में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी उस समय कथेरिया बांदा जिले के बबेरू कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात थे। मृतका के भाई केपी सिंह की शिकायत के आधार पर बबेरू कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई जिसमें आरोप लगाया गया कि अतिरिक्त दहेज की मांग की वजह से शकुन ने यह कदम उठाया।

नीति आयोग की बैठक में नहीं आए बिहार के सीएम नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम हुए शामिल

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हो रही नीति आयोग की बैठक को लेकर राजनीति खूब हो रही है। विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों की ओर से इसका बहिष्कार किया गया है। वहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। इसको लेकर भी अब चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि, बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने किया। महत्वपूर्ण बैठक से नीतीश कुमार की अनुपस्थिति का कारण तत्काल पता नहीं चल सका है।

नीति आयोग, जो केंद्र सरकार का शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है, में अध्यक्ष के रूप में प्रधान मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, कई केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल (एलजी) और कई केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य हैं। सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बैठक में हिस्सा लेने और अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को उजागर करते हुए पीएम मोदी के सामने एक प्रेजेंटेशन देने का निर्देश दिया गया है। हालाँकि, कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह पहली बार नहीं है कि सीएम केंद्र सरकार के शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक नीति आयोग की बैठक में उपस्थित नहीं होंगे। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि सीएम पहले भी बैठक में शामिल नहीं हुए थे और बिहार का प्रतिनिधित्व तत्कालीन डिप्टी सीएम ने किया था। इस बार भी दोनों डिप्टी मीटिंग के लिए गए। इसके अलावा, राज्य से चार सदस्य आयोग के सदस्य हैं और वे उपस्थित थे। लोकसभा में 12 सीटों (एनडीए की 293 में से) के साथ, जेडी (यू), आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी; 16 सीटें) के साथ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस साल के आम चुनावों में, भाजपा ने 543 सदस्यीय लोकसभा में 240 सीटें जीतीं और लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाई, साथ ही पीएम मोदी ने भी प्रधानमंत्री पद की हैट्रिक हासिल की।

ग्रामीण विकास हेतु बजट में 1.80 लाख करोड़ की व्यवस्था

बजट में रुपए 7.5 लाख तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना, घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए रुपए 10 लाख तक के ऋण की वित्तीय सहायता और उस पर ब्याज छूट के लिए ई-वाउचर देना युवाओं को आकर्षित कर सकता है, किंतु वही प्रशिक्षित युवा व शिक्षित युवा बाजार में अपने लिए या बाजार उसके लिए कितने अवसर उपलब्ध करा पाता है का प्रश्न रोजगार परकता पर अभी प्रश्न ही है जिसका उत्तर खोजना ही होगा।

भारत ग्रामीण राष्ट्र है और ग्रामीण आर्थिक विकास की समृद्धि के बिना विकसित भारत का सपना अधूरा है। वित्तमंत्री की प्रशंसा की जानी चाहिए कि ग्रामीण विकास हेतु बजट में 1.80 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई है, जो ग्रामीण अवसंरचना को विकसित करेगा। रक्षा के क्षेत्र में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) का सबसे बड़ा हिस्सा व्यय करना समय की मांग हो सकती है, किंतु शिक्षा व स्वास्थ्य में अभी भी सार्वजनिक निवेश अत्यधिक कम है, जो चिंताजनक है। यद्यपि रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़ की सौगात बजट में दी गई है। लेकिन रेल सहित परिवहन विभाग में नवाचार, नए साधन, नई रेलगाड़ियां की बात स्पष्ट नहीं है। अर्थशास्त्र की भाषा में बात की जाए तो नौकरी पेशा व्यक्ति हतोत्साहित हुआ है, जिसे बचत करने, नया घर बनाने आदि का कोई प्रोत्साहन बजट में नहीं मिला, क्योंकि पुराने टैक्स स्लैब में 80-सी में बचत का दायरा हो या होम लोन की लालसा सब सिमट गई है, जिससे थोड़ा कर बचाने के लिए नए कर रिजीम में प्रवेश बचत को हतोत्साहित करेगी और अर्थव्यवस्था इन्फ्लेशनरी प्रेशर अर्थात महंगाई का दबाव बढ़ाएगी। साथ ही राजकोषीय घाटे का लक्ष्य तीन प्रतिशत जिसे बहुत पहले लक्षित किया गया था वर्तमान के 4.9 प्रतिशत राजकोषीय घाटे का लक्ष्य प्रतिशत होना उन निर्णय व अधिनियमों की विफलता का संकेत है।

एक तरफ घरेलू बचतों का हतोत्साहन व दूसरी तरफ निजी निवेश पर अल्पकाल में 20 प्रतिशत तथा दीर्घकाल में 12.5 प्रतिशत तक का बड़ा ब्याज देना तर्क संगतता के रूप में अर्थव्यवस्था को असंतुष्ट करने जैसा है। यह संतुलन अत्यधिक उपभोग की अवस्था को जन्म दे सकता है, जिसके लिए संभवतः भारतीय अर्थव्यवस्था तैयार नहीं है।

आज भी एक रुपए में सर्वाधिक हिस्सा लगभग 27 प्रतिशत उधारियों से प्राप्त हो रहा है, वहीं व्यय में 19 प्रतिशत ब्याज अदायगी में। इस पर नवीन विकल्प तलाशने होंगे प्रतिव्यक्ति आय को सिर्फ जनसंख्या में भाग देकर बढ़ता हुआ देखना विकास नहीं हो सकता। बल्कि मनरेगा जैसी अन्य योजनाओं का निर्माण कर नवीन आय का निर्माण करना आवश्यक है। अन्यथा रुपए 48.21 लाख करोड़ राशि का बड़ा बजट भारतीय अर्थव्यवस्था के एक हिस्से को तथा एक निश्चित जनसंख्या के जहाज को विकास की ऊंची उड़ान (टेक ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट)की ओर तो ले जाएगा, लेकिन इसे लैंड कै से और कहां करना है का विकल्प नहीं होगा और पूर्ण जनसांख्यिकी लाभांश नहीं मिल सकेगा।

गत मंगलवार को अंतरिम बजट 2024-25 के चार प्रमुख स्तंभों-गरीब, किसान, महिला और युवा का उल्लेख करते हुए वित्तमंत्री ने नौ नवीन प्राथमिकताओं के साथ भारतीय अर्थ व्यवस्था को तीसरी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था बनाने की बात, विकसित भारत की संकल्पना के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट प्रस्तुत किया है।

कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को जिसकी वृद्धि दर महज 1.8 प्रतिशत गत वर्ष रही हो प्रथम वरीयता इस बजट में मिलना महत्वपूर्ण है, किंतु आंकड़ा गत धन आवंटन में कृषि फिर से पीछे रह गई जिससे चार प्रतिशत की वृद्धि दर पाना निश्चय ही मुश्किल काम होगा। जबकि कृषिगत भूमि का संकुचन निरंतर बढ़ता जा रहा है और कृषि पर आय नहीं अन्न की निर्भरता बढ़ती जा रही है। कृषि हेतु उत्पादकता से अधिक अनुकूलनीयता का उल्लेख करना आकर्षित करता है, जिसमें राष्ट्रीय सहकारिता नीति को व्यवस्थित करना दलहन व तिलहन में आत्मनिर्भरता पाना आदि पुरानी बातों को ही समाहित किया गया है। लेकिन जलवायु अनुकूलित नई किस्म के बीज विकसित करना और सब्जी उत्पादन हेतु नई सप्लाई चैन बनाना सराहनीय कदम है। अब चुनौती यह है कि कृषि शोध व कृषि में सार्वजनिक निवेश का बढ़ाना आवश्यक है।

विकसित भारत हेतु औद्योगिक विकास के रूप में औद्योगिक पार्क व औद्योगिक गलियारों को विकसित करने का बजट प्रावधान निश्चित ही आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देगा। बशर्ते अवसंरचना विकास नीतिगत निर्णय व समय विलंबना का शिकार न हो। वित्तमंत्री ने एक बड़ी धनराशि लगभग 11.11लाख करोड़ पूंजीगत रूप में व्यय करने की बात कही है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें विनिर्माण व संरचना विकास हेतु व्यय प्रस्तावित है, ध्यान रहे कि इससे शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा, किन्तु यह ग्रामीण वातावरण को और दूषित न करे। शहरों में शहरी हाट के विकास से अधिक ग्रामीण साप्ताहिक हाट को प्रोत्साहन देने से मुद्रा वेग व मुद्रा गुणक अधिक बलवान होगा, जिसकी आवश्यकता भी है। ऊर्जा सुरक्षा हेतु प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना उत्साहवर्धक है। साथ ही परमाणु रिएक्टरों का अनुसंधान व विकास व थर्मल पावर प्लांट में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग ऊर्जा संरक्षण व निर्माण को बल देगा, जिसकी आवश्यकता पर्यटन व नवाचार में आंध्र प्रदेश व बिहार को वरीयता देने के अलावा बजट में कुछ नहीं है, जो भारत जैसी अर्थव्यवस्था का विकास की राह में अवरुद्धता उत्पन्न कर सकते हैं। साथ ही अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हुए पूंजीगत आवंटन की अधिक धनराशि का व्यय जनकल्याण हेतु पूंजीगत व्यय में कटौती कर-के ही संभव होगा। जो वर्तमान में विकासशील भारत के हित में नहीं होगा। इन दोनों में संतुलन समय की मांग है। अगली पीढ़ी के सुधारों में सम्मिलित दायरों जैसे भूमि संबंधी कार्य एनपीएस, वात्सल्य, आदि में शिक्षा स्वास्थ्य परिवजन पर्यावरण को भी सम्मिलित किया जा सकता था।

द्वितीय प्राथमिकता में पुनः रोजगार व प्रशिक्षण का सम्मिलित करना प्रधानमंत्री पैकेज योजना का अंग है, जिसमें कामगारों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना तथा 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना कौशलविकास केन्द्र की पुरानी अवधारणा को आगे बढ़ाना ही है। अर्थात इसमें कुछ नया नहीं है। जब तक उनकी उत्पादकता पर काम न किया जाए, एक कारण यह है कि आर्थिक सर्वेक्षण में जब वित्तमंत्री स्वयं स्वीकार कर चुकी हैं कि राष्ट्र में 50 प्रतिशत स्नातक रोजगार योग्य नहीं हैं इसका दोष किसे दिया जाए? नीतियों में खामियां पाठ्यक्रम का गैर व्यवसायीकरण या शिक्षा व्यवस्था। बजट में रुपए 7.5 लाख तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना, घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए रुपए 10 लाख तक के ऋण की वित्तीय सहायता और उस पर ब्याज छूट के लिए ई-वाउचर देना युवाओं को आकर्षित कर सकता है, किंतु वही प्रशिक्षित युवा व शिक्षित युवा बाजार में अपने लिए या बाजार उसके लिए कितने अवसर उपलब्ध करा पाता है का प्रश्न रोजगार परकता पर अभी प्रश्न ही है जिसका उत्तर खोजना ही होगा। इसी क्रम में समावेशी मानव संसाधान व सामाजिक न्याय की अवधारणा में समावेशी तत्व महत्वपूर्ण है जिसे लघु व कुटीर उद्योगों में बजट आवंटन को बढ़ाकर मुद्रा ऋण की राशि को 10 से 20 लाख करना, 5 वर्षों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना आदि सहायकसिद्ध होंगे और अर्थव्यवस्था विकास कीओर अग्रसर होगी।

बच्चों को एसएसबी ने कराया सीमा दर्शन

ककरहवा, देवरिया (जीकेबी)। एसएसबी 43वीं वाहिनी सीमा चौकी ककरहवा के जवानों की ओर से स्कूली बच्चों को मंगलवार को सीमा भ्रमण कराया गया। बार्डर पर बच्चों को दोनों तरफ कि भौगौलिक स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। एसएसबी ककरहवा के जवानों की ओर से विलेज वाइब्रेंट कार्यक्रम के तहत गोद लिए गए गांव ककरहवा में स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को सीमा भ्रमण कराया गया। एसएसबी की ओर से छात्र-छात्राओं को भारत नेपाल के अंतरराष्ट्रीय सीमा के महत्वपूर्ण पहलुओं से रूबरू करवाया गया। इस दौरान ककरहवा बीओपी के सहायक कमांडेंट अखिलेश कुमार ने स्कूली बच्चों को सीमा के महत्व और नो मेन्स लैंड के नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दो देशों की सीमा अति संवेदनशील होती है। सीमा नियमों का पालन हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। इस दौरान बच्चों को जीरो लाइन, बॉर्डर पिलर आदि के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही सीमा से 10 गज दोनों तरफ अंतरराष्ट्रीय नो मेंस लैंड के बारे में बताया गया। इसमें दोनों देश में से कोई भी देश किसी तरह का निर्माण नहीं कर सकता हैं। उन्होंने कहा कि देशभक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए आप भी शिक्षित बनकर देश को बेहतर बनाने में अपना योगदान दें।

वन कैडेट वन ट्री के तहत लगाए पौधे

बस्ती(जीकेबी)। महिला पीजी कॉलेज में मंगलवार को एनसीसी कैडेट्स ने महाविद्यालय परिसर में वन कैडेट, वन ट्री कैंपेन के तहत पौधरोपण किया।

महाविद्यालय की प्राचार्य प्रो. सुनीता तिवारी ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाना एक मात्र विकल्प है। यह सभी का दायित्व है, इसे मिलकर निभाने से ग्लोबल वार्मिंग जैसे संकटों से छुटकारा पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय परिसर को हरा-भरा बनाने का सभी को संकल्प लेना होगा। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से महाविद्यालय को जिले में नंबर वन बनाया जाएगा। प्राचार्य ने परिसर में विश्व प्रसिद्ध आम्रपाली प्रजाति के आम की पौध लगाया। एनसीसी केयरटेकर डॉ. संतोष यदुवंशी ने फाईकस, एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. रघुवर पांडेय आम, डॉ. सीमा सिंह ने चमेली, डॉ. रुचि श्रीवास्तव ने चंपा, डॉ. प्रियंका पांडेय ने हथजोड़ और पूनम यादव ने अशोक का पौधा लगाया। इस मौके पर डॉ. सुहासिनी सिंह, डॉ. नूतन यादव, डॉ. बीना सिंह, डॉ. सुधा त्रिपाठी, प्रियंका सिंह, नेहा परवीन, मोनी पांडेय आदि मौजूद रहीं।

नगर पालिका बोर्ड की बैठक में निर्णय

शासन की मंशानुरूप होगा सभी वार्डों का कायाकल्प

बस्ती(जीकेबी)। नगर पालिका बोर्ड की शनिवार को अध्यक्ष नेहा वर्मा की अध्यक्षता में बैठक की गई। मुख्य रूप से गृहकर व जलकर में वर्तमान मांग पर एक अगस्त से 30 सितंबर तक के लिए 10 प्रतिशत छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया। नगर पालिका बोर्ड की बैठक को संबोधित करते हुए विधान परिषद सदस्य सुभाष यदुवंश ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप सभी वार्डों का कायाकल्प किया जाए। इससे आम जनमानस को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। अध्यक्ष नेहा वर्मा ने कहा कि वार्ड के सभासदों की मांग पर सभी वाडों के नालों व नालियों की साफ-सफाई के साथ ही विद्युत व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से सही कराया जाएगा। कहा कि वर्तमान में जेसीबी से मुख्य नालों की सफाई कराई जा रही है।

नगर पालिका के जमीनों पर किये गये अवैध कब्जे को चिन्हित कर उसे मुक्त कराया जाएगा। कहा कि स्वच्छ व सुंदर बस्ती बनाने के लिए नगर पालिका प्रशासन कटिबद्ध है। सभासद परमेश्वर शुक्ला उर्फ पप्पू व सभासद प्रफुल्ल श्रीवास्तव के द्वारा बस्ती जनपद का नाम बशिष्ट नगर किये जाने का प्रस्ताव दिया गया जिसपर बोर्ड के मेम्बरों ने स्वीकृति दी। अधिशाषी अधिकारी जितेंद्र सिंह ने कहा कि सभी विकास के कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से कराए जा रहे हैं।

शिविरों के माध्यम से कर रही डेंगू मरीजों की जांच स्वास्थ्य विभाग की टीम

पडरौना(जीकेबी)। बारिश के बाद डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। डेंगू मरीजों के लिए मेडिकल कॉलेज और सीएचसी पर बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। जिले में पिछले साल डेंगू के 106 मरीज मिले थे। इस साल अब तक पांच डेंगू के मरीज पाए गए हैं। डेंगू के पॉजीटिव मिले मरीजों के घरों के आसपास एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जा रहा है। स्वास्थ्य टीम मरीजों के गांवों में कैंप कर लोगों की जांच कर रही है। दूसरी तरफ सीएमओ ने निजी अस्पतालों को भी डेंगू मरीजों का ब्यौरा देने का निर्देश दिया है।

बारिश का मौसम चल रहा है। इसमें डेंगू लार्वा अधिक पनपने का खतरा बना रहता है, जिससे लोग डेंगू की चपेट में आ जाते हैं। लोगों को डेंगू से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी कर ली है। इन दिनों विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के तहत स्वास्थ्य टीमें गांव-गांव में घर-घर जाकर बुखार आदि के मरीजों की जानकारी जुटा रही है। स्वास्थ्य टीम की ओर से लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। पिछले साल 106 डेंगू के मरीज पाए गए थे। इस साल अब तक पांच मरीज डेंगू से संक्रमित मिले हैं। डेंगू को लेकर सीएचसी पर पांच-पांच बेड आरक्षित किए गए हैं। जबकि मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी के बगल में बने आइसोलेशन वार्ड को डेंगू वार्ड के रूप में तब्दील कर दिया गया है। वहीं, सीएमओ डॉ. सुरेश पटारिया ने निजी अस्पतालों को डेंगू के मामलों की जानकारी विभाग को देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी निजी अस्पताल में डेंगू का मरीज मिलता है तो उसका पूरा ब्यौरा देना होगा। इसके साथ ही डेंगू जांच के लिए एलाइजा ही मान्य है। कोई भी अस्पताल में किट से डेंगू की पुष्टि न करें।

अनफिट वाहनों के संबंध में बीएसए को परिवहन विभाग ने लिखा पत्र

महराजगंज(जीकेबी)। जिले के स्कूल-कॉलेज में लगे अनफिट वाहनों पर कार्रवाई को लेकर परिवहन विभाग कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। एआरटीओ ने डीआईओएस और बीएसए को पत्र लिखकर स्कूलों पर शिकंजा कसने के लिए कहा है। परिवहन विभाग ने 73 से अधिक स्कूलों की सूची भी अधिकारियों को सौंपी है। परिवहन विभाग के रिकॉर्ड में करीब 310 स्कूल वाहन पंजीकृत हैं। इसमें बस, वैन व अन्य वाहन शामिल हैं। हैरत की बात ये है कि पिछले दिनों तक करीब 130 स्कूली वाहन ऐसे थे, जिनकी फिटनेस नहीं हो सकी थी, जबकि वह सड़कों पर फरार्टा भर रहे थे। इन वाहनों में न तो कैमरे लगे थे और न ही फर्स्ट एड बॉक्स था। स्कूलों की बदइंतजामी और परिवहन विभाग की लापरवाही बच्चों के लिए खतरा बनी हुई थी। बीते दिनों नौतनवां में एक निजी स्कूल की गाड़ी बच्चों के साथ स्टेयरिंग फेल होने के कारण पलट गई थी। जिसमें अभिभावकों ने भी डीएम, एसपी, डीआईओएस व बीएसए को ज्ञापन दिया। इस-के बाद विभाग भी सक्रिय हो गया है कि अनफिट वाहन न चलने पाएं। विभाग ने इसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक व बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर सहयोग मांगा है।

बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रवण गुप्ता के अनुसार, जिले में स्कूल वाहन से हो रही दुर्घटना को देखते हुए एआरटीओ ने पंजीकृत स्कूल के वाहनों की फिटनेस पर सहयोग मांगा था। वह दिया जाएगा।

लेफ्ट लिबरल की टूलकिट में दो मारक हथियार

हिंसा-घृणा के वास्तविक पीड़ितों को ही अपराधी घोषित करना लेफ्ट-लिबरल का कोई नया शगल नहीं है। जब अमेरिका 2001 में विकराल 9/11 आतंकी हमले का शिकार हुआ, तब इसी कुनबे ने उसे तत्कालीन बुश प्रशासन की सोची-समझी साजिश बताकर प्रस्तुत किया। भारत भी ऐसे नैरेटिव का शिकार हुआ है। वर्ष 2008 में मुंबई पर वीभत्स आतंकी हमले को कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने संघ की साजिश बताकर पाकिस्तानी आतंकियों को वाकओवर देने का प्रयास किया था। कांग्रेस द्वारा गढ़ा गया फर्जी हिंदू/भगवा आतंकवाद सिद्धांत भी लेफ्ट-लिबरल टूलकिट का हिस्सा है। जब 27 अक्टूबर, 2013 को पटना में मोदी की जनसभा को निशाना बनाया गया तो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इसे भाजपा का ही किया-धरा बताया। उस हमले में छह लोगों की मौत हो गई थी। ऐसा ही नैरेटिव 14 फरवरी, 1998 को कोयंबटूर के शृंखलाबद्ध बम धमाकों के बाद भी बना था। तब भाजपा के शीर्ष नेता लालकृष्ण आडवाणी को लक्षित करते हुए इस हमले में 58 लोगों की जान चली गई थी। तब भी कांग्रेस ने इस जिहादी हमले का आरोप संघ-भाजपा पर मढ़ दिया था। लेफ्ट-लिबरल टूलकिट में जहां हिंसा-घृणा के शिकार वर्ग को अपराधी बनाने का उपक्रम होता है, वही उन्माद-नफरत फैलाने के आरोपित या इसके लिए प्रत्यक्ष-परोक्ष जिम्मेदार व्यक्ति-संगठन को क्लीनचिट देने का नैरेटिव भी होता है। भड़काऊ भाषणों के लिए कुख्यात और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपित अब्दुल नासिर मदनी को जेल से बाहर निकालने हेतु वर्ष 2006 में होली की छुट्टी के दौरान 16 मार्च को केरल विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर कांग्रेस और वामपंथियों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था।

ऐसी ही हमदर्दी यह समूह इशरत जहां, याकूब मेमन, अफजल गुरु और बुरहान वानी जैसे घोषित आतंकियों के प्रति भी दिखा चुका है। लेफ्ट-लिबरल में विरोधाभास उसकी संज्ञा के अनुरूप है। लेफ्ट अर्थात वामपंथी अवधारणा में ह्यलिबरलह्ल यानी उदारता का कोई स्थान नहीं होता। वामपंथी शासन व्यवस्था वस्तुतः हिंसा, असहमति का दमन और मानवाधिकारों के उल्लंघन का पर्याय रही है। लेनिन-स्टालिन-माओ-जोंग आदि इसके उदाहरण हैं। लेफ्ट-लिबरल का उभार 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद हुआ। इस तबके में असंतुष्ट वर्ग का उदय हुआ, जिसे ह्यवोकह्ल कहा जाता है। भले ही उनके पास कोई सर्वमान्य वैकल्पिक व्यवस्था का खाका न हो, मगर वे विश्व में सैकड़ों वर्षों से स्थापित समाज को छल-बल के सहारे ध्वस्त करना चाहते हैं। अमेरिका में ट्रंप पर गोली चलाने वाला और भारत में देश को आग में झोंकने की धमकी देने वाले इसी विषैली मानसिकता के ही प्रतिनिधि हैं।

लेफ्ट-लिबरल तबके को तीन प्रकार के लोगों-खालिस वामपंथी, कट्टरपंथी मुस्लिम और अराजक तत्वों से आवश्यक खाद-पानी मिलता है। एक-दूसरे के प्रति असहिष्णु होने के बाद भी वामपंथी और कट्टरपंथी मुस्लिम अक्सर दुनिया को अस्थिर बनाने और बहुलतावाद को ध्वस्त करने के अभियान में जुट जाते हैं।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर थामस मैथ्यू क्रुक्स ने जानलेवा हमला किया। ट्रंप बाल-बाल बच गए और हमलावर सुरक्षाबलों के हाथों मारा गया। हमलावर बाइडन समर्थकों के दूषित प्रचार के प्रभाव में था। क्रुक्स को ट्रंप से इतनी घृणा हो गई कि वह उनकी हत्या के लिए आमादा हो गया। यह सब तथाकथित लेफ्ट लिबरल के नफरती अभियान का परिणाम था, जिसका शिकार केवल अमेरिका ही नहीं, अपितु भारत सहित शेष विश्व भी है। लेफ्ट-लिबरल तबके को तीन प्रकार के लोगों-खालिस वामपंथी, कट्टरपंथी मुस्लिम और अराजक तत्वों से आवश्यक खाद-पानी मिलता है। एक-दूसरे के प्रति असहिष्णु होने के बाद भी वामपंथी और कट्टरपंथी मुस्लिम अक्सर दुनिया को अस्थिर बनाने और बहुलतावाद को ध्वस्त करने के अभियान में जुट जाते हैं।

भारत में वामपंथियों ने अंग्रेजों और जिहादी मानसिकता वाले मुस्लिमों के साथ मिलकर इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान को जन्म दिया। इसी तरह ईरान को आधुनिक और उदारवादी बनाने का प्रयास कर रहे शाह मोहम्मद रजा पहलवी (1941-1979) को अपदस्थ कर वामपंथी और कट्टरपंथी मुस्लिम गठजोड़ ने अराजकता फैलाई। आज ईरान शरीयत अधीन इस्लामी गणतंत्र है, जहां रोज मानवाधिकारों की हत्या और महिलाओं का दमन होता है। अब पाकिस्तान और ईरान में न तो वामपंथ का कोई नामलेवा है और न ही चीन की वामपंथी शासन-व्यवस्था में इस्लाम का कोई स्थान। देखा जाए तो लेफ्ट-लिबरल की टूलकिट में दो मारक हथियार हैं। पहला, सफेद झूठ, अर्धसत्य और तथ्यों को विरूपित कर अपने वैचारिक-राजनीतिक विरोधियों का दानवीकरण और उनके प्रति हिंसा-घृणा का भाव पैदा करना। दूसरा, दोषियों के बजाय हिंसा-घृणा के शिकार समूह-व्यक्ति-राष्ट्र को ह्यअपराधीह्ल बनाकर प्रस्तुत करना। अमेरिका के साथ फ्रांस भी इसका दंश झेल चुका है और अब इंग्लैंड में भी यही लहर चलती दिख रही है। ट्रंप पर हमला क्यों हुआ? अमेरिकी चुनाव में ट्रंप को उनके विरोधी ह्यअमेरिकी लोकतंत्र के लिए खतराह्ल बता रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप के लिए लेफ्ट-लिबरल समूह जैसा विषवमन करता है, ठीक वैसा ही दुष्प्रचार भारत में प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए किया जाता है। लोकसभा चुनाव में नैरेटिव बनाया गया कि यदि मोदी जीते तो यह देश का अंतिम चुनाव होगा और संविधान और आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। यहां तक कि कांग्रेस के शीर्ष नेता और लेफ्ट-लिबरल की कार्बन-कापी बन चुके राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार में कह दिया कि भाजपा के जीतने पर देश में आग लग जाएगी। कुछ वर्ष पहले एक चुनावी सभा में राहुल प्रधानमंत्री मोदी को डंडे मारने की बात भी कर चुके हैं। बीते दिनों जब पीएम के काफिले पर चप्पल फेंकी गई तो उन्होंने कहा कि अब लोगों ने प्रधानमंत्री से डरना छोड़ दिया है। विरोधी दलों की मानसिकता यहां तक पहुंच गई है कि पुलवामा में आतंकी हमलों को भी भाजपा की साजिश बताया गया। इसी कुनबे से जुड़े वकील प्रशांत भूषण ने पिछले साल यहां तक कह दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए राम मंदिर पर पुलवामा जैसा आतंकी हमला करा सकते है। वास्तव में, यह नैरेटिव 500 वर्ष पश्चात पुनर्निर्मित राम मंदिर पर संभावित जिहादी हमले होने की स्थिति में न केवल हिंदुओं को लांछित करने, अपितु असली दोषियों को मासूम बताने के प्रपंच का हिस्सा है।

कुछ राजनैतिक संदेश व संभावनाएं पैदा करता अंबानी के बेटे का 93 दिन का विवाह पर्व

विवाह के खर्च के बारे में लोगों के अलग-अलग अनुमान हें जो हजार करोड़ से लेकर 5-10 हजार करोड़ तक के खर्च बताते हैं। यह अनुमान स्वाभाविक है क्योंकि इटली में पूरा द्वीप कई दिनों तक किराए पर लेना, विवाह के अंतिम दिन समारोह में आए मेहमानों को दो-दो करोड़ रुपए के गिफ्ट देना यह सामान्य घटना नहीं और खर्चों के पांच हजार करोड़ के अनुमान को सही ठहराती है। ऐसा लग रहाहै कि जैसे अंबानी के थुलथुल बेटे की शादी कोई राष्ट्रीय पर्व बन गया हो और जिसका खर्च कहने को अंबानी कर रहे हों परन्तु देश के आम नागरिक को समें अपना हिस्सा अदा करना पड़ रहा है। विवाह के आयोजनों के दौर में अंबानी ने जियो फोन की दरों को बढ़ा दिया और एक प्रकार से देश के जियो ग्राहकों के ऊपर विवाह टैक्स लगा दिया। स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री का दोस्त वही हो सकता हे जो आपदा में अवसर खोज लेता हो। इस शादी से और उसकी चर्चा से देश में कई प्रकार की मनोवृत्तियां पैदा हुईं।

अंबानी के वैभवपूर्ण विवाह ने जहां एक तरफ आम जन के मानस में भोग विलास दिखावा, फिजूलखर्ची के कीटाणु पैदा कर दिल व दिमाग को विकृत किया है, उसके साथ ही बाजार के लिए नए द्वार भी खोल दिए हैं। इन सब दिखावों के ऊपर जो पैसा खर्च होगा अंततः वह बाजार में ही जाएगा। इसलिए शायद मीडिया ने इन खबरों को आकर्षक बनाकर परोसा है क्योंकि मीडिया के मालिक भी वही उद्योगपति व व्यापारी हैं मीडिया अगर एक सामान्य व्यक्ति अपने परिवार के विवाह में पांच-से दस लाख रुपए खर्च करता होगा तो वह अब अपनी क्षमता से बाहर जाकर भले ही उसे अचल संपत्ति बेचना पड़े, कर्ज लेना पड़े, पर वह 20-30 लाख रुपए खर्च करेगा। उसके बच्चे उसे बाध्य करेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक वर्ष में देश में एक करोड़ शादियां होती हों और उनमें से 50-60 लाख शादियां मध्यमवर्गीय परिवारों की हों तो दश के बाजार को आसानी से पांच से दस लाख करोड़ का व्यापार मिल जाएगा। मनोवृत्तियों को बिगाड़कर, भोग और जलसे और दिखावे की मानसिकता को तैयार कर पैसा कमाने केकई प्रकार के प्रयोग पिछले वर्षों से मीडिया ने शुरू कराए हैं। विवाह की वर्षगांठ, विवाह के 25 साल, 50 साल और इन्हें एक बार फिर से नए विवाह के समान बारात और जुलूस से लेकर सभी नाटकीय पुनरावृत्ति शुरू कराई गई जिन पर दस-बीस लाख का खर्च मामूली तौर पर होता है। अब ऐसा समय आएगा जिसमें जितनी शादियां होंगी उनसे ज्यादा शादियों की वर्षगांठ होगी। जन्म दिवस के उत्सव, मुडन का उत्सव और न जाने कितने प्रकार के उत्सव शुरू करा दिए गए जिनमें दिखावे व प्रचार ने मध्यम वर्ग को उलझा दिया। इस उत्सवधर्मिता ने एक ओर लाभ व्यापारजगत को पहुंचाया है वह यह है कि मध्यमवर्गीय व उच्च मध्यमवर्गीय वर्ग अपने सारे, सामाजिक सरोकारों को भूल जाता है व केवल इन समारोहों के विसर्जन में उनमें शिरकत करने में फंसा रहता है। अगर उसके जीवन के कालखण्ड का सामान्य अध्ययन किया जाए तो साल के लगभग सौ दिन, समाज के उच्च व मध्यमवर्ग के लोग विवाह, विवाह की वर्षगांठ, जन्मदिन, कथा और भण्डारे, तीर्थदर्शन आदि पर खर्च करता है और बकाया समय अपने पारिवारिक दायित्व की पूर्ति के लिए ड्यूटी पर जाता है। याने वह आम समाज से शारीरिक और मानसिक रूप से कट जाता है तथा अपने समाज या देश के बारे में सोचने-विचारने, उसमें सहभागिता करने का न समय उसके पास होता है और न ही उसका मन होता है।

आम आदमी ऐसे भारी महंगी शदियां जिसमें तथाकथित वीवीआईपी या सेलिब्रेटी, शामिल हों के प्रति लालायित आकर्षित होता है और इसका परिणाम यह होगा कि ये और उनके बच्चे अपनी शादियों में इस दिखावे के लिए क्षमता से अधिक खर्च करेंगे। मुझे स्मरण है कि लगभग 35-36 वर्ष पहले, जब माधवराव सिंधिया की बेटी की शादी का आयोजन ग्वालियर में हुआ था तो हेलीकाप्टर से फूल बरसाए गए थे। में व मेरे उस समय के मित्र शरद यादव

मुकेश अंबानी के बेटे अनन्त और राधिका के लगभग 93 वें दिन के विवाह पर्व का समापन हो गया और बकाया देश की तो मैं नहीं जानता, परन्तु मेरे जैसे समाचार पत्र के पाठकों को कुछ सुकून मिला। वरना तीन माह से कब मंगनी हुई, कब फलनी हुई, कहां टजली में पीवेडिंग हुई, द्वीप किराए पर लिए, कितने हवाई जहाज, कितने बम्बई के फिल्मी दुनिया के नचइए-गवइए शामिल हुए, इन्हीं उबाई वाली खबरों से मीडिया भरा पड़ा था।

उस शादी के कुछ दिनों के बाद ग्वालियर यात्रा पर थे तथा हमारे समाजवादी साथी विष्णुदत्त तिवारी के मकान पर बैठे थे, तब एक गांव का किसान मिलने के लिए आया था जो अंचल की पिछड़ी जाति गुर्जर समाज से था और उसने हम लोगों से पूछा कि हेलीकाप्टर का किराया कितना लगता है। हम लोगों ने बताया कि बहुत पैसा लगता है और क्यों जानना चाहते हो तो उसने बताया कि मैं मेरी बेटी की शादी में हेलीकाप्टर से फूल बरसाना चाहता हूं। हमने उससे पूछा कि इतना पैसा तुम कहां से लाओगे? तो उसने उत्तर दिया कि दस एकड़ जमीन बेच दूंगा पर हेलीकाप्टर से फूल बरसाऊंगा। ऐसे खर्चीले व दिखावटी आयोजन का आमजन के मानस पर कितना विपरी प्रभाव पड़ता है यह इस घटना से समझा जा सकता है और उसके बाद पिछल्ले वर्षों में अपनेकों ऐसे समाचार मीडिया में आए हैं जहां गांव के किसान और पिछड़ी जाति के लोगों ने फूल बरसाने या वर-वधू की विदाई के लिए हेलीकाप्टर किराए पर लिए।

अंबानी के इस विवाह का निमंत्रण उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, केन्द्र सरकार के प्रधानमंत्री मंत्रियों और विरोधी दलों के नेताओं को भी दिया था, जिनकी देर सवेर सत्ता में आने की संभावनाएं हैं या जिनके उनके साथ राजनीति व व्यापारिक रिश्ते हैं जो सांसद या विधानसभा के माध्यम से उन्हें लाभ या हानि पहुंचा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तो उनके समारोह में न केवल सम्मिलित हुए बल्कि मीडिया के अनुसार दो घंटा चालीस मिनट वहां रहे। मैं मान सकता हूं कि चूंकि दोनों गुजरात के हैं और प्रधानमंत्री की राजनीति व धीरूभाई अंबानी के परिवार का गहरा रिश्ता होगा, परंतु एक देश का प्रधानमंत्री एक उद्योगपति के विवाह पर्व में पौने तीन घंटे रहे क्या यह देश के प्रशासन तंत्र को खुला संदेश नहीं है? और सत्ता प्रतिष्ठान व उद्योग प्रतिष्ठान के गहरे रिश्तों का खुलासा नहीं करता।फिर प्रधानमंत्री की इस विवाह यात्रा का खर्च किसने उठाया? प्रधानमंत्री की यात्रा पर खर्च, विमान, सुरक्षा आदि मिलाकर करोड़ों में होता है। क्या प्रधानमंत्री ने यह खर्च निजी कोष से उठाया है? क्या यह खर्च अंबानी समूह ने उठाया है? या देश की गरीब जनता को भोग और जलसों के लिए प्रेरित करने क खर्च भी सरकारी खजाने यानी जनता ने उठाया है? अगर प्रधानमंत्री ने यह खर्च स्वतः उठाया हो या अभी भी इसकी राशि जता करतें तो कम से कम यह उनकी नैतिकता होगी परन्तु यह होगा नहीं।

मुकेश अंबानी के बेटे अनन्त और राधिका के लगभग 93 वें दिन के विवाह पर्व का समापन हो गया और बकाया देश की तो मैं नहीं जानता, परन्तु मेरे जैसे समाचार पत्र के पाठकों को कुछ सुकून मिला। वरना तीन माह से कब मंगनी हुई, कब फलनी हुई, कहां टजली में पीवेडिंग हुई, द्वीप किराए पर लिए, कितने हवाई जहाज, कितने बम्बई के फिल्मी दुनिया के नचइए-गवइए शामिल हुए, इन्हीं उबाई वाली खबरों से मीडिया भरा पड़ा था।

मुकेश अंबानी ने कांग्रेस के संसदीय दल की नेता श्रीमती सोनिया गांधी को भी यह निमंत्रण दिया बताया जा रहा हे कि उनके घर पर एक घंटे रहे। एक निमंत्रण देने में एक घंटे का समय कुछ आश्चर्यजनक भी है और कुछ राजनैतिक संदेश व संभावनाएं भी पैदा करता है। गुजरात के एक राजनेता देवेन्द्र यादव तो आरोप लगाया है कि अंबानी ने कांग्रेस के साथ कुछ डील कर ली है और उसी का एक हिस्सा हे कि राहुल गांधी ने गुजरात में जाकर कहा कि अब गुजरात में सरकार कांग्रेस की आएगी। उनकी यह असामयिक घोषणा कुछ चौंकाने वाली तो है क्योंकि उद्योग जगत ईश्वर प्रदत्त दोनों हाथों से बांटता है। एक से सत्ता के लिए और दूसरे से सत्ता के संभावितों के लिए। यद्यपि वैयक्तिक निमंत्री पत्र इंडिया गठबंधन के बड़े हिस्सेदार ममता बनजी, अखिलेश यादव, शरदपवार, उद्धव ठाकरे, तो इस विवाह में शामिल हुए ही, साथ ही लालू प्रसाद यादव तो संपूर्ण परिवार फौज के साथ शामिलहुए। अगर इसे गणित से तौला जाए तो इंडिया गठबंधन का बहुमत विवाह समारोह में शामिल हुआ।

मेरी राय में ऐसी शादियों पर देश में रोक लगनी चाहिए जो अमीरी व विलासित का नग्न प्रदर्शन करती हे। मुकेश अंबानी के ऊपर इस विलासिता के खर्च के लिए विशेष टैक्स लगाया जाना चाहिए और वह दिन सुखद दिन होगा जब मीडिया स्वतः अपने लाभ व व्यापार का मोह छोड़कर ऐसी शादियों को प्रचारित करना बंद करेगा। वरना अभी तो देश में एक सुनियोजित अभियान चल रहा हे कि हर व्यक्ति, हर युवा के मन में अंबानी पैदा कर दिया जाए। जो संपत्ति से भले ही अंबानी नहीं हो पर दिमागी तौर पर उस सभ्यता का दुमछल्ला होगा व विषमता के लिए अपना आदर्श मानेगा। सामाजिक संगठनों को चाहिए कि ये शादियों की इन परंपराओं, दिखावों, फिजूल खर्ची और बेहतर हो कि रात्रि की शादियों पर रोक लगाएं। आजकल एक पीवेडिंग नाम का चलन शुरू हुआ है। यह एक प्रकार से शादी पूर्व शादी या शादी के समान ही खर्चीली परम्रा की शुरुआत की गई है।

गोविप्रा की 126वीं समीक्षा बैठक संपन्न

गोरखपुर। गत दिनों गोरखपुर विकास प्राधिकरण की 126वीं बैठक मण्डलायुक्त/गोरखपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष, अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में आहूत की गयी। बैठक में 125वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन की समीक्षा की गयी। रामगढ़ताल के किनारे पैडलेगंज से आर.के.बी.के. सहारा स्टेट तक ताल रिंग रोड एवं ताल फ्रण्ट विकसित किये जाने के कार्य में अत्यधिक विलम्ब होने के लिये इस कार्य हेतु अधिकृत अवर अभियन्ता को तत्काल निलम्बित करने तथा अधिशासी अभियन्ता एंव सहायक अभियन्ता को प्रतिकूल प्रविष्टि दिये जाने के निर्देश दिये गये।

भाटी विहार निर्माण कार्य की प्रगति में सुधार न होने के लिये सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को भी प्रतिकूल प्रविष्टि दिये जाने के निर्देश दिये गये।

मुख्यमंत्री की अपेक्षानुसार नई जेट्टी एवं गोरखपुर आई के निर्माण की सर्वसम्मति से सहमति दी गयी। बैठक में अग्रेतर फर्टिलाइजर के निकट अधिग्रहित भूमि पर राप्तीनगर विस्तार टाउनशिप एवं स्पोर्ट्स सिटी योजना का अनुमोदन प्रदान किया गया। लच्छीपुर में प्राधिकरण की 4.72 एकड़ रिक्त भूमि पर कुश्मी एवेन्यू (ग्रुप हाउसिंग अपार्टमेन्ट) योजना अनुमोदित की गई। हरसेवकपुर नं.-1 में 3.30 एकड़ पर ग्रुप हाउसिंग बनाए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई साथ ही प्राधिकरण के विस्तारित क्षेत्र की महायोजना अतिशीघ्र तैयार किए जाने तथा महायोजना तैयार होने तक सर्वे कराकर मानचित्र स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। महायोजना में चिन्हित गैर आवासीय वाले विनियमितिकरण से प्रभावित क्षेत्रों में जन सामान्य के मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि नियमानुसार निर्धारित आवश्यक शुल्क लेते हुए मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही की जाए। खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी फेज-2 में निर्मित आवासों के विनियमितिकरण के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) गोरखपुर की अध्यक्षता में समिति गठित कर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

भू-उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव पर निर्देशित किया गया कि शासन से भू-उपयोग परिवर्तन होने के पश्चात ही आवश्यक कार्यवाही की जाए। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सेवानिवृत्त कार्मिकों को राशिकरण के भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश को अंगीकृत करते हुये नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये गये।

निधन पर शोकसभा

गोरखपुर। पशुधन प्रसार अधिकारी नितेश सिंह के धर्मपत्नी कामना सिंह के असामयिक निधन पर पशुधन प्रसार अधिकारी संघ के जिलाध्यक्ष टी. एन. सिंह, मंत्री अखिलेश पांडेय, उपाध्यक्ष मयंक श्रीवास्तव, पूर्व जिलाध्यक्ष बृजेंद्र कुमार सिंह, पूर्व मंत्री शैलेन्द्र पांडेय, अजय सिंह, गो सेवक वरूण बैरागी, तथा वेटनरी फार्मासिस्ट संघ के जिलाध्यक्ष उमा सिंह, मंत्री विनय सिंह, मंडलीय अध्यक्ष पी.पी.एन. राज, मंडलीय मंत्री कमलेंद्र प्रताप सिंह, प्रांतीय उपाध्यक्ष मनोज शाही, पूर्व प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष उपेन्द्र धर दूबे, दुर्गेश सिंह आदि ने शोक संवेदना व्यक्त कर दिवंगत आत्मा की शांति हेतु दो मिनट का मौन रखते हुए ईश्वर से प्रार्थना किया।

हमारी गलतियों से कही टूट न जाना,
हमारी शरारत से कही रूठ न जाना,
तुम्हारी चाहत ही हमारी जिंदगी हैं,
इस प्यारे से बंधन को भूल न जाना...

एक दिवसीय भव्य माटीकला सेमिनार का आयोजन 30 को

गोरखपुर। महाप्रबन्धक उ.प्र. माटीकला बोर्ड लखनऊ के निर्देश के क्रम में एक दिवसीय भव्य माटीकला सेमिनार का आयोजन परम्परागत कारीगरों के उत्साहवर्धन एवं उन्हे प्रोत्साहित करने व उनको और अधिक उर्जित बनाने के उद्देश्य से दिनांक 30जुलाई दिन मंगलवार को कम्बल कारखाना खजनी गोरखपुर में दिन के 11 बजे से आयोजित किया जा रहा है जिसमें मण्डल के सभी जनपदों के माटीकला के कामगार सादर आमंत्रित है इस सेमिनार में माटीकला से सम्बन्धित तकनीकी, शिल्पकारी एवं व्यवसायिक विषयों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा विधिवत जानकारी प्रदान की जायेगी तथा मण्डल के जनपदों के निःशुल्क विद्युत चालित चाक हेतु चयनित लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया जायेगा। सेमिनार में इच्छुक माटीकला के कारीगर निःशुल्क प्रतिभाग कर इसका लाभ उठा सकते है। अतः इच्छुक माटीकला के कामगार उक्त नियत स्थान व समय पर पहुच कर माटीकला से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर सकते है

विशेष जानकारी हेतु 8528062765 नम्बर पर सम्पर्क किया जा सकता है। उक्त जानकारी परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी ए.के. पाल ने दी है।

कारगिल दिवस: सपने थे भाई की कलाई पर रक्षासूत्र बंधन के मिली गौतम गुरुंग के शहादत की खबर

गोरखपुर (जीकेबी)। 26 जुलाई को पूरा देश कारगिल के शहीदों की शान और उनके शहादत को याद करेगा। 1998 में करगिल युद्ध के दौरान गोरखपुर के लाल गौतम गुरुंग ने भी अपनी शहातद दी थी। युद्ध में उनकी बहादुरी और अदम्य- शौर्य व साहस को देखते हुए राष्ट्रपति ने मरणोपरांत उन्हें सेना मेडल से नवाजा था। उनकी बहन आज भी उनके लिए खरीदी राखी संजो कर रखी हैं। जिस दिन राखी खरीदी थी, अगले दिन शहादत की खबर आ गई। 26 जुलाई को पूरा देश कारगिल के शहीदों की शान और उनके शहादत को याद करेगा। 1998 में कारगिल युद्ध के दौरान गोरखपुर के लाल गौतम गुरुंग ने भी अपनी शहातद दी थी। युद्ध में उनकी बहादुरी और अदम्य- शौर्य व साहस को देखते हुए राष्ट्रपति ने मरणोपरांत उन्हें सेना मेडल से नवाजा था। उनकी बहन आज भी उनके लिए खरीदी राखी संजो कर रखी हैं। जिस दिन राखी खरीदी थी, अगले दिन शहादत की खबर आ गई। आज भी परिजन उन्हें याद कर भावुक हो जाते हैं। लेकिन, उन्हें गर्व रहता है कि उनके बेटे ने देश के लिए लड़ते-लड़ते अपनी जान न्योछावर कर दी थी। ये वक्त 4 अगस्त 1988 का था, जब करगिर युद्ध पर अपने चरम पर था। इसी दौरान युद्ध के बीच में ही गौतम गुरुंग को सूचना मिली कि उनके सात से आठ साथी एक बंकर में फंसे हैं और पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग और लांचर से हमले हो रहे हैं। साथियों को बचाने के लिए सीधे बंकर में चले गए और साथियों को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे कि अचानक रॉकेट लांचर सीधे बंकर पर आ गिरा। कमर पर गंभीर रुप से चोट लगने के बाद भी उन्होंने अपने सभी आठ साथियों को सकुशल बंकर से बाहर निकाल कर सुरक्षित कर दिया। गंभीर रुप से घायल गौतम अगले दिन, 5 अगस्त(1998) को शहीद हो गए। पिता ने भी अपने बेटे के देश सेवा और जज्बे का सम्मान आगे बढ़ाते हुए शहादत के बाद सरकार की तरफ से मिली आर्थिक सहायता से कईयों की जिंदगी संवारने का जरिया बना दिया।

बहन आज भी संभाल कर रखी हैं राखी

छोटी बहन मिनाक्षी आज भी अपने भाई का राखी को संजो कर रखा है। 4 अगस्त 1998 को ही मिनाक्षी ने अपने भाई को भेजने के लिए राखी खरीदी थी। उस वर्ष 7 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार था। राखी खरीदने के लिए अगले दिन 5 तारीख को ही भाई के शहादत की खबर आ गई। मिनाक्षी राखी भेज भी नहीं पाई थी। सभी से उन्होंने राखी को सहेज कर आज भी अपने पास रखा है।

शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़, हर-हर महादेव से गूंजता रहा परिसर

गोरखपुर(जीकेबी)। सोमवार के दिन से ही सावन की शुरूआत हुई है। समापन भी सोमवार के दिन ही होगा। अबकी बार श्रावण मास 29 दिनों का है। पवित्र महीना सावन 22 जुलाई से प्रारंभ होकर 19 अगस्त तक चलेगा। इस बार सावन का महीना बहुत ही शुभ और दुर्लभ योग में शुरू हुआ है। सात दशकों के बाद ऐसा मुहूर्त बना है। सावन में भगवान शिव की आराधना और पूजा करने पर विशेष लाभ मिलता है। गोरखपुर के शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। भगवान भोलेनाथ को समर्पित श्रावण मास की शुरूआत सोमवार से हो गई। सावन के पहले सोमवार पर गोरखनाथ मंदिर सहित आस-पास के प्रमुख मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्त बड़ी संख्या में सुबह से ही मंदिरों में दर्शन के लिए लाइन लगाए गए थे। इन मंदिरों में सुबह की आरती के लिए एक दिन पहले ही तैयारियां कर ली गई थीं।

मंदिरों में हर हर महादेव के गूंज होती रही। श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए कतारों में लगे हुए हैं। इस बार के सावन मास की खास बात है कि इसकी शुरूआत सोमवार को हुई और समापन भी सोमवार को हो रहा है। इस साल शिव भक्तों को सावन के पांच सोमवार व नौ विशेष योग का पुण्य मिलेगा।

ज्योतिषाचार्य घनश्याम पांडेय ने बताया शिव महापुराण के अनुसार, श्रावण मास का हर एक दिन भगवान शिव की पूजन के लिए शुभ है, खास है। बताया कि सामान्यतः रुद्राभिषेक करने के लिए भक्तों को शिववास देखने की आवश्यकता होती है, लेकिन श्रावण मास में ये बंधन लागू नहीं होता है। इस महीने के किसी भी दिन और किसी भी समय बिना तिथि व मुहूर्त देखे रुद्राभिषेक कर सकते हैं।

अपनी बारी की प्रतीक्षा में प्रतीक्षारत श्रद्धालु

नया नेतृत्व शायद राज्य से भय, आतंक व अराजकता के वातावरण को दुरुस्त कर सकेगा

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने के जब डॉ.मोहन यादव ने यह कहना शुरू किया था कि राज्य में कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा उस समय प्रदेशवासियों में यह उम्मीद जगी थी कि प्रदेश को मिला नया नेतृत्व शायद राज्य से भय, आतंक व अराजकता के वातावरण को दुरुस्त कर सकेगा। परन्तु राज्य के हालात कानून व्यवस्था से लेकर भ्रष्टाचार तक अभी भी न केवल जस के तस बने हुये हैं बल्कि अपराधियों द्वारा अंजाम दी जाने वाली कुछ घटनाओं से तो ऐसा प्रतीत होने लगा है गोया सत्ता बदलने या मुख्यमंत्री की कानून व्यवस्था सम्बन्धी किसी चेतावनी का अपराधियों पर कोई असर ही नहीं। हद तो यह है कि प्रदेश में घटी अनेक बड़ी आपराधिक घटनाओं में सत्तारूढ़ भाजपा के लोगों के शामिल होने के भी प्रमाण मिलते रहे हैं। तभी विपक्ष को भी पूछना पड़ रहा है कि प्रदेश में होने वाली हर बड़ी आपराधिक घटनाओं के पीछे कहीं न कहीं बीजेपी से जुड़े लोग शामिल होते पाए गए हैं। तो क्या सरकार और पार्टी इस दिशा में कोई कदम उठाने वाली है? विपक्ष यह भी पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार को जंगलराज के टैग से मुक्ति कब मिलेगी? और विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति पर होने वाले अत्याचार कब समाप्त होंगे? पिछले दिनों मध्य प्रदेश के रीवा जिले में इलाहबाद मार्ग पर स्थित मंगावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दबंगों द्वारा अपनी दबंगई का वह प्रदर्शन किया गया जो शायद आजतक उस बिहार व उत्तर प्रदेश जैसे उन राज्यों में भी नहीं हुआ जहाँ लालू यादव व अखिलेश यादव के राज को जंगल राज कहकर यही सत्ताधारी भाजपाई आज भी सम्बोधित किया करते हैं। रीवा जिले के हिनौता क्षेत्र में हुई इस घटना में गुंडों ने डंपर से बजरी फेंककर दो महिलाओं को जिंदा दफनाने की कोशिश की। इस घटना में ममता पांडे और आशा पांडे नाम की दो महिलाएं बजरी के ढेर में कमर और गर्दन तक दब गई थीं। जिन्हें स्थानीय लोगों ने फावड़े की सहायता से बजरी के ढेर में से बाहर निकाल कर उनकी जान बचाई। इन महिलाओं को बेहोशी की हालत में इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। यदि स्थानीय लोग मानवता का प्रदर्शन करते हुये उन महिलाओं को समय रहते बजरी के ढेर से बाहर न निकालते तो दोनों महिलाएं जिंदा ही दफ़्न हो जातीं। बताया जा रहा है कि इस गांव में एक सड़क निर्माण योजना को लेकर महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही थीं। उन महिलाओं का दावा है कि चूँकि यह जमीन उन्हें सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई थी इसीलिये वे उस जमीन पर सड़क निर्माण का विरोध कर रही थीं। और जब उन्होंने सड़क निर्माण रोकने की कोशिश की तो उन पर जानलेवा हमला किया गया। पीड़ित महिलाओं ने गौकरण प्रसाद पांडे, महेंद्र प्रसाद पांडे सहित अन्य कई व्यक्तियों पर हमला करने और डंपर चालक पर उन्हें जिंदा दफनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।

मोहन यादव सरकार से पहले शिवराज चौहान सरकार में भी इस राज्य में मानवता को शर्मसार करने वाली दबंगई की कई शर्मनाक घटनायें हो चुकी हैं। गत वर्ष जुलाई माह में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर बिकौरा गांव में पंचायत के लिए नाली का निर्माण कार्य चल रहा था। उस समय रामकृपाल पटेल नामक व्यक्ति पास के एक हैंडपंप पर नहा रहा था। बताया जाता है कि उसी समय दलित समुदाय के एक व्यक्ति दशरथ अहिरवार ने हंसी मजाक के माहौल में ग्रीस लगे हाथ से आरोपी रामकृपाल पटेल को छू लिया। तभी गुस्साया पटेल नहाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे मग में पास में पड़ा मानव मल भर लाया और इसे दशरथ अहिरवार के सिर और चेहरे सहित पूरे शरीर पर भी लगा दिया। पीड़ित दलित दशरथ अहिरवार ने यह भी आरोप लगाया कि पटेल ने इस दौरान उसे जाति के आधार पर अपमानित भी किया। और जब उसने मामले की सूचना पंचायत को दी और बैठक बुलाई। तो पंचायत ने उल्टे उसी पर 600 रुपये का जुमार्ना भी लगा दिया।

यह वही मध्य प्रदेश राज्य है जहाँ गत वर्ष जुलाई में सीधी से भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ला के प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत प्रवेश शुक्ला नामक एक युवक ने एक आदिवासी युवक के मुंह व चेहरे पर पेशाब करते अपनी वीडियो बनवाई थी। बाद में आरोपी प्रवेश शुक्ला के विरुद्ध बहारी थाने में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 294 (अश्लील हरकतें), 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। साथ ही आरोपी के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई भी शुरू की गई थी। मानवता को आहात करने वाली इस घटना ने पूरे मध्य प्रदेश को शर्मसार कर दिया था। इस घटना की वीडिओ भी वायरल हुई थी। इस घटना का जिक्र विदेशी मीडिया ने भी किया था। वैसे भी मध्य प्रदेश पूरे देश में दलितों के साथ अपराध के मामलों में तीसरे स्थान पर है।

एक दो दशक पहले के खासकर उत्तर प्रदेश व बिहार में अन्य दलों के शासन को आज भी गुंडा राज कहकर याद करने वाली भाजपा के शासन में आखिर कौन सा अपराध नहीं हो रहा है? पुलिस कस्टडी में लोगों की संदिग्ध अवस्था में हत्यायें हो जाना क्या अराजकता की निशानी नहीं? गैंग रेप, अपहरण दलितों व अल्पसंख्यकों पर जुल्म क्या यह बेहतर कानून व्यवस्था के लक्षण हैं? जेल में गैंगवार और हत्यायें बेहतर कानून व्यवस्था की परिचायक तो हरगिज नहीं? दरअसल भाजपा नेताओं व सरकार की प्राथमिकतायें कुछ और ही हैं। छोटे मोटे अपराधों को लेकर समुदाय विशेष के लोगों के घरों व व्यवसायिक ठिकानों पर बुलडोजर चलाकर दूसरे समुदाय के लोगों की वाहवाही लूटना यानी एक की बबार्दी दिखाकर दूसरों को खुश करना यही इनकी लोकप्रियता का शार्ट कट है। अन्यथा

एक दो दशक पहले के खासकर उत्तर प्रदेश व बिहार में अन्य दलों के शासन को आज भी गुंडा राज कहकर याद करने वाली भाजपा के शासन में आखिर कौन सा अपराध नहीं हो रहा है? पुलिस कस्टडी में लोगों की संदिग्ध अवस्था में हत्यायें हो जाना क्या अराजकता की निशानी नहीं? गैंग रेप, अपहरण दलितों व अल्पसंख्यकों पर जुल्म क्या यह बेहतर कानून व्यवस्था के लक्षण हैं? जेल में गैंगवार और हत्यायें बेहतर कानून व्यवस्था की परिचायक तो हरगिज नहीं? दरअसल भाजपा नेताओं व सरकार की प्राथमिकतायें कुछ और ही हैं।

डंपर से बजरी फेंक कर दो महिलाओं को जिंदा दफ़्न करने से बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? देश के तमाम मीडिया ने इस घटना को ह्यतालिबानी कृत्य ह्य का नाम दिया। यहाँ आखिर बुलडोजर क्यों नहीं चला? यदि इस तरह के दुस्साहसिक गुंडा राज के दौर को भी सुशासन बताने की कोशिश की जाये फिर आखिर जंगल राज किसे कहा जाये?

कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देना राज्य का दायित्व

कामगारों के पास बीमारी, दुर्घटना, वृद्धावस्था, रोग और बेरोजगार आदि के कारण उत्पन्न जोखिमों का सामना करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं होता है और संकट के समय में उनकी सहायता करने के लिए जीविका का वैकल्पिक साधन का अभाव होता है। इसलिए कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देना राज्य का दायित्व है। 19वीं शताब्दी के अंत तक अधिकांश राज्य अपने को पुलिस राज्य रखकर ही संतुष्ट थे। उनका मुख्य काम शांति एवं व्यवस्था कायम रखना था। वे सामाजिक सुरक्षा का कार्य व्यक्तियों और व्यक्तियों के समूहों के जिम्मे छोड़ रखे थे। लेकिन धीरे-धीरे राज्य के स्वभाव में बुनियादी बदलाव आया और उसकी प्राथमिकता में सामाजिक सुरक्षा की औपचारिक व्यवस्था शीर्ष पर हो गई।

लॉयड जार्ज के प्रथम मंत्रित्व काल में इंग्लैंड की सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के तहत सामाजिक बीमा चालू किया जिसके तहत बूढ़े, अवकाश प्राप्त व्यक्ति, विधवाएं और बेरोजगार लाभ उठाते थे। इस योजनान्तर्गत स्कूल में बच्चों को दूध देने, गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं को दूध और विशेष भोजन देने, निःशुल्क डाक्टरी सहायता और निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा के लिए अच्छी छात्रवृत्तियों की व्यवस्थाएं की गयी हैं। गौर करें तो संपूर्ण यूरोपीय देशों में विस्तृत सामाजिक सुरक्षा लागू है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी जनता को लाभ पहुंचाने संबंधी विस्तृत सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चालू हैं। भारतीय संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा एक समग्र अधिगम है जिसका निर्माण व्यक्ति को आर्थिक अभाव से बचाने और व्यक्ति के खुद के लिए तथा उसके आश्रितों के लिए उन्हें आर्थिक अनिश्चितता की स्थिति से बचाने हेतु एक न्यूनतम सुनिश्चितता के लिए किया गया है। यह तथ्य भारत के नीति-नियन्ताओं द्वारा पहचाना गया और तदनुसार, सामाजिक सुरक्षा से संबद्ध विषयों को राज्य के नीति-निदेशक तत्व और समवर्ती सूची में संबद्ध किया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 41 में कार्य के अधिकार शिक्षा और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता की व्यवस्था की गयी है। अनुच्छेद 42 में कार्य की उचित और मानवीय परिस्थिति और मातृत्व राहत की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में भी सामाजिक सुरक्षा और बीमा, रोजगार और बेरोजगार, कार्य परिस्थिति , भविष्य निधियां, नियोक्ताओं का दायित्व, कर्मगारों की क्षतिपूर्ति अवैधता, श्रम कल्याण, वृद्धावस्था पेंशन और मातृत्व लाभ का उल्लेख है। र्

सरकार द्वारा अपने नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की ढेरों योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। लेकिन बढ़ती जनसंख्या के कारण इसे विस्तार देने की जरूरत है। सामाजिक सुरक्षा का अभिप्राय ऐसी सभी सेवाओं, साधनों और सुविधाओं से है जो नागरिकों को दी जाती है जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर होता है। सामाकि सुरक्षा श्रम कल्याण का एक मुख्य संघटक है और उसे निरन्तर विकास प्रक्रिया के एक अंग के रूप में देखा जाा है। सामाजिक सुरक्षा वैश्वीकरण ओर उसके कारण होने वाले संरचनात्मक और तकनीकी परिवर्तनों से उपजी चुनौतियों से निबटने में अधिक सकारात्मक रवैये के कारण निर्माण में सहायता प्रदान करती है। सामाजिक सुरक्षा में यह परिकल्पना को जाती हे कि नागरिको को सभी प्रकार के सामाजिक जोखिमों से रक्षा की जाएगी जो उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में अनावश्यक मुश्किलें उत्पन्न करती हैं।

भारत में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक सामाजिक सुरक्षा प्रभाग की स्थापना की है जो कर्मगार सामाजिक सुरक्षा नीति एवं योजनाएं बनाने और क्रियान्वित करने का कार्य करता हैभारत में ढेरों सामाजिक सुरक्षा कानून लागू है मसलन कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम-1948(ईएसआई एक्ट)कर्मचारी क्षति पूर्ति अधिनियम-1923 (डब्लूसी एक्ट), कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम-1952(ईपीडीएण्डएमपी एक्ट), प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम-1961 (एमबी एक्ट), ग्रैच्युटी भुगतान अधिनियम-1972 (पीजी एक्ट), वैयक्ति क्षति (आपात उपलब्ध) अधिनियम-1962, वैयक्ति क्षति (प्रतिकर बीमा) अधिनियम-1963 और नियोजक दायित्व अधिनियम-1938 इत्यादि। सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आज देश में पोषण सुरक्षा की देखभाल राष्ट्रीय तैयार मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, समन्वित बाल विकास योजना, किशोरी शक्ति योजना, किशोर लड़कियों के लिए पोषण कार्यक्रम और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना चलायी जा रही है। राष्ट्रीय तैयार मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम लगभग पूरे भारत में चल रहा है। समन्वित बाल विकास योजना का विस्तार भी हो रहा है। 11 से 18 वर्ष तक की उम्र की लड़कियों के पोशण एवं स्वास्थ्य संबंधी विकास के लिए सरकार ने किशोरी शक्ति विकास योजना को हर जगह लागू कर दिया है।

एक अरसे से श्रम आन्दोलन के तहत सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम लागू करने की मांग की जाती रही जिसे सरकार ने 2005 के माध्य में लागू कर दिया। इस इस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति जो न्यूनतम मजदूरी पर आकस्मिक श्रम करने के लिए इच्छुक है वह 15 दिनों के अंदर स्थानीय जन कार्य में रोजगार पाने के लिए पात्र होगा। इसके अंतर्गत लोगों को वर्ष में उसके निवास से एक किमी के भीतर सौ दिनों का काम दिये जाने का प्रावधान लागू किया गया है। हालांकि इस योजना में काफी भ्रष्टाचार की बात उठती है फिर भी सामजिक सुरक्षा के लिहाज से यह योजना प्रभावकारी साबित हुआ है। सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अंत्योदय अन्न योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। राज्यों से अत्यंत ही गरीब परिवारों की पहचार करने का कार्य अंत्योदय योजना के तहत किया गया है। इन परिवारो को गेहूं और चावल दिया जाता है। सामाजिक सुरक्षा के तहत रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन रणनीति के तहत सरकार द्वारा स्वरोजगार योजना और दिहाड़ी रोजगार योजना चलाया जा रहा है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को संशोधित कर लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन करने के लिए सुनिश्चित किया गया है। असंघटित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा से सुसज्जित करने के लिए राष्ट्रीय उद्यम आयोग की स्थापना एक पारदर्शी निकाय के रूप में की गयी है। सामाजिक सुरक्षा के तहत भारत सरकार ने आवास नीति 1992 संसद में प्रस्तुत की। अगस्त 1994 में संसद ने इसका अनुमोदन कर दिया। राष्ट्रीय आवास नीति का प्रमुख लक्ष्य आवास हीन व्यक्तियों, विस्थापितों निराश्रित महिलाओं, अनुसूचित जातियों और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए वातावरण निर्मित करना तथा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। वर्तमान केन्द्र सरकार द्वारा चार करोड़ से अधिक लोगों को आवास उप4लब्ध कराया गया है। आने वाले दिनों में तीन करोड़ और आवास निर्मित करने का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया है। इंदिरा गांधी आवास योजनान्तर्गत आवास निर्माण के लिए सरकार द्वारा ऐसे लोगों को सहायता दिया जाता है जिनका मुखिया विधवा, अविवाहित, महिलाएं, विकलांग अथवा शरणार्थी है। या जो अत्याचारों अथवा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं या जो परिवार विकास योजनाओं से विस्थापित या खानाबदोश हैं। सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा असंघटित ग्रुप बीमा योजना, वन बंधु कल्याण योजना, अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास योजना, विकलांगों के लिए योजना, जनश्री बीमा योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना चलाई जा रही है। सामाजिक सुरक्षा के तहत समाज के कमजोर वर्गों को कानूनी सहायता देने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। यह प्राधिकरण देश भर में कानूनी सहायता कार्यक्रम और योजनाएं लागू करनेके लिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण पर दिशा निर्देश जारी करता है। सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुभारम्भ की है जिसका उद्देश्य लाभकारी योजनाओं निर्धनों और सीमांत लोगों को पहुंचने में सक्षम बनाना है। लोगों का स्वास्थ्य रहे इसके लिए सरकार आयुष्मान योजना को लागू की हेजो गरीबों के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। निश्चित रूप से सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से सामाजिक सुरक्षा मजबूत हुई है। बेहतर होगा कि सरकार सामाजिक सुरक्षा का दायरा का विस्तार करे जिससे सर्वाधिक नागरिकों का कल्याण हो।

किसानों को उद्यमी बनाने की योजना

भारतीय खेती की परंपरा को जाने वाली विदेशी खेती माना जाता है। लेकिन यह महज मान्यता है, क्योंकि देशी खेती में रसायनों, रासायनिक उर्वरकों और विदेशी बीज का इस्तेमाल नहीं होता है और नयी तकनीक और वैज्ञानिक ढंग से की जाने वाली खेती में रसायनों, जहरीले कीटनाशकों और महंगे उर्वरकों का इस्तेमाल उत्पादन बढ़ाने के बावत किया जाता है। केन्द्र सरकार की नयी पहल आधुनिक खेती के जरिये किसानों को उद्यमी बनाने के लिए है। दुनिया में वैज्ञानिक एवं तकनीक पद्धति से खेती करना समझदारी और मुनाफे देने वाली खेती के रूप में समझा जाता है। जाहिर तौर पर भारतीय परम्परागत खेती विदेशी केन्द्र सरकार की नयी पहल होगी, जिसमें किसानों को कृषि तकनीकों और वैज्ञानिक विधियों से परिचित कराना और उन्हें अपना ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है।

जानकारी के मुताबिक केन्द्र सरकार ने किसानों को उद्यमी के तौर पर तैयार करने का फै सला किया है। इसके बावत देश के हर जिले में ऐसी टीम बनाई जाएगी, जिसमें खेती से ताल्लुक रखने वाले सभी क्षेत्रों के लोग होंगे। केन्द्र सरकार के माध्यम से मुहैया कराई गई सूचना या जानकारी के अनुसार बनाई जाने वाली टीम में किसानों के अलावा कृषि वैज्ञानिक कारखानों के विशेषज्ञ, कृषि विभाग और प्रशासन के अधिकारियों को शामिल किया जाना है। इसके अलावा किसान उत्पादक संघटन (एफपीओ)कृषि सखी, ड्रोन दीदी और स्वयं सहायता समूह में बेहतर कार्य करने वाले किसानों और महिलाओं को भी इससे जोड़ने की बात कही गयी है। केन्द्र सरकार की यह पहल राज्य सरकार और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइ-सीएआर)के अधीन आने वाले सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों के वैज्ञानिक मिलकर इसके लिए काम करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक (कृषि विस्तार) डा. उधम सिंह के मुताबिक देश भर में 731 कृषि, विज्ञान (केवीके) संचालित हो रहे हैं। इन केन्द्रों पर तैनात कृषि वैज्ञानिकों की मदद से किसानों कोउद्यमी बनाने और फसलों को बर्बाद होने से बचाने का खाका तैयार किया जा रहा है। यदि केन्द्र सरकारी की यह किसान कल्याण योजना कारगर हुई तो इससे उन करोड़ों किसानों को फायदा हो सकता है जो खेती को घाटे का सौदा बताकर छोड़ चुके हैं या अभी तक बदहाली की जिन्दी गुजार रहे हैं।

केन्द्र सरकार तकनीक आधारित खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने का कार्य करने की बात कहती है। एनडीए पिछले शासन के दौरान किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। एनडीए पिछले शासन के दौरान किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जिनमें पशुपालन मधुमक्खी, मछली पालन, सुअर पालन जैसी व्यवसायिक योजनाएं शामिल हैं। गौरतलब है केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की तमाम योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही हैं वे किसानों के लिए बहुत मुफीद नहीं हो पा रही है। उसकी वजह है पहली यह कि पानी की कमी, पानी की कमी की वजह से देश में सिंचाई समस्या आज भी बहुत बड़ी समस्या है। जिन इलाकों में नहरों के जरिये सिंचाई होती है वहां खेती के समय नहर में पानी न आना बहुत बड़ी समस्या है। इसका सीधा असर फसल के उत्पादन पर पड़ता है। इसी तरह उत्तम किस्म के बीजों की अनुपलब्धता मेड़बंदी, और वर्षा जल का संरक्षण न होने की वजह से जिस तरह क परिणाम की उम्मीद थी वैसे नहीं आ पाए। खेती से ताल्लुक रखने वाले तजुर्बेकारों का मानना है कि रासायनिक खेती से बढ़ रही समस्याओं और बीमारियों के मद्देनजर केन्द्र सरकार यदि राज्य सरकारों के साथ मिलकर रासायनिक खेती मुक्त भारत का अभियान चलाए तो जलवायु परिवत्रन, बढ़ती बीमारियों और तमाम तरह के प्रदूषणों एवं समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। इसलिए किसानों को उद्यमी बनाने का बेहतर तरीका अपनाया जाना चाहिए। किसानों को जलवायु अनुकूल खेती जिसे प्राकृतिक या जैविक खेती कहा

किसानों को अभी तक बाजार की जरूरत के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती थी। इस टीम के जरिये किसानों तक यह बात पहुंचाई जाएगी कि किस फसल को उगाने से फायदा होगा और किनसे नुकसान। इतना ही नहीं, फसल तैयार होने के बाद जिले ीार की खपत के बाद जो अन्न या उत्पाद बच जाएगा उसमें जो बढ़िया उत्पाद होगा उसके निर्यात या बीज के रूप में इस्तेमाल करने के लिए सुनिश्चित किया जा सकेगा। ऐसे किसानों का चयन टीम करेगी जो बेहतर उत्पाद और जलवायु परिवर्तन के अनुरूप खेती कर दूसरे किसानों के लिए नजीर बन सकते हैं।

जा रहा है, को हर किसान को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की भी जरूरत है। इससे उर्वरकों, बीजों और छिड़काव करने वाले यंत्रों पर दी जाने वाली अरबों रुपए की सब्सिडी की बचत होगी और देश की सेहत सुधारने में मदद मिलगी। इसके अलावा गांवों से गरीबी ही नहीं भागेगी, बल्कि भुखमरी, कुपोषण, अशिक्षा, बेरोजगारी और पलायन जैसी तमाम समस्याओं से धीरे-धीरे छुटकारा मिलने लगेगा। जाहिर तौर पर प्रदूषित अन्न, फल, सब्जियों और दूध के सेवन से मानसिक और शारीरिक बीमारियां ज्यादा बढ़ रही हैं।

केन्द्र सरकार की यह पहल किसानों को उद्यमी बनाने में कितनी सफल होती हे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन टीम का गठन कर यदि ईमानदारी से किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का कार्य किया जाएगा और उसके परिणाम यदि बेहतर आते हैं तो यह किसानों की माली हालत को सुधारने में मील का पत्थर भी साबित हो सकता है। अभी तो किसान अपने उत्पदकों को औने-पौने दाम पर बचने के लिए मजबूर रहता है। इस पहल के मुताबिक हर जिले में टीम के गठन से पिछले आंकड़ों का अध्ययन कर फसल का जनपद में मांग और खपत का पता करना आसान हो सकता है। जानकारी के अनुसार, टीम के माध्यम ये यह पता किया जाएगा कि आगामी सीजन में किस फसल की कितनी बुवाई करनी चाहिए और किस किस्म की फसल लेना बेहतर होगा।

गौरतलब है किसानों को अभी तक बाजार की जरूरत के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती थी। इस टीम के जरिये किसानों तक यह बात पहुंचाई जाएगी कि किस फसल को उगाने से फायदा होगा और किनसे नुकसान। इतना ही नहीं, फसल तैयार होने के बाद जिले ीार की खपत के बाद जो अन्न या उत्पाद बच जाएगा उसमें जो बढ़िया उत्पाद होगा उसके निर्यात या बीज के रूप में इस्तेमाल करने के लिए सुनिश्चित किया जा सकेगा। ऐसे किसानों का चयन टीम करेगी जो बेहतर उत्पाद और जलवायु परिवर्तन के अनुरूप खेती कर दूसरे किसानों के लिए नजीर बन सकते हैं।

भारत उर्वरक उत्पादन में दुनिया के शीर्ष दस देशों में शामिल है। निर्यात के नजरिये से लगातार उर्वरकों का उत्पादन और बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन भारतीय खेती के लिए यह घाटे का सौदा है। जाहिर तौर पर केन्द्र सरकार के जरिये उर्वरकों पर छूट के बावजूद किसानों के लिए यह घाटे का सौदा है। इससे उपजाऊ जमीन और वायुमंडल पर जो विपरीत असर पड़ता हे उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। केन्द्र सरकार की यह नयी पहल तभी ज्यादा कारगर हो सकेगी जब फसल के लिए लागत कम से कम हो। बाजार के समझना और उसके अनुकूल फसल बोने की निश्चित करना ठीक है, लेकिन लागत में कमी कर-के किसानों का ज्यादा भला किया जा सकता हे। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1.23 ट्रिलियन भारतीय रुपए से अधिक मूल्य के उर्वरकों का आयात किया गया। केन्द्र सरकार की नयी पहल को कारगर बनाने के लिए जरूरी है कि गांवों से पलायन को रोका जाए। जाहिर तौर पर पलायन रोकने में रासायनिक खेती कारगर नहीं रही है। इसलिए रसायनिक खेती की उपयोगिता और प्रासंगिकता पर भी गौर करने की जरूरत है। नाम मात्र की लागत में अधिक उत्पादन और जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने में प्राकृतिक खेती ही सबसे ज्यादा फायदेमंद और उपयोगी है। इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। करोड़ों किसानों के जरिये जो खेती की जा रही है उससे किसानों को फायदा नहीं मिलता है और न यह सेहत के लिए ही मुफीद मानी जाती है।

लागत बहुत ज्यादा और उत्पादन बहुत कम। मेरी समझ से सरकार यदि किसानो का भला करना चाहती है और किसान उद्यमी बनकर खुशहाल जिन्दगी गुजारे तो इसके लिए जरूरी है बहुत कम लागत में बेहतर उत्पाद देने वाली प्राकृतिक खेती को हर तरह से प्रोत्साहित करना ही चाहिए।

जिस तरह से फैक्टरी घाटे में होने पर उसका सारी भरपाई सरकार करती है, इसी तरह किसानों की खेती में घाटा लगने पर सरकार को भरपायी करनी चाहिए। जो सिफारिशें डा.एम.एस. स्वातीनाथन ने न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन के संबंध में की थीं उसे हूबहू लागू करना चाहिए। इससे देश का किसान खुशहाल नहीं होगा, बल्कि समाज से भी तमाम तरह की समस्याओं, दुश्वारियों और बीमारियों से भी छुटकारा मिल सकता है।

‘बजट मोदी के सपनों का भारत की झलक दिखती है’

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब 23 जुलाई मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया तो किसी को अमृतकाल और विकसित भारत की आहट मिली, तो किसी को वही रटी रटाई पश्चाताप जो पिछले 10 सालों से होती आई है और अगले 15 सालों तक रहने वाली है, यदि इस बीच गठबंधन की गांठ नहीं खुली तो। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट बताया और कहा कि यह अगले पांच साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा। लेकिन उनकी बातों में, बजट अभिभाषण में, और बजट प्रस्तावों में मीन मेख निकालने वाले नेताओं की कमी नहीं दिखी।

बावजूद इसके केंद्रीय बजट 2024 एक संतुलित बजट है, क्योंकि इसमें महिलाओं, युवाओं, गरीबों, किसानों के हित को सामने रखकर विभिन्न आवश्यक व लोकहितकारी घोषणाएं की गई हैं। देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी के अमृत काल वाले विकसित भारत के संकल्प की प्रतिबद्धता को दोहराता हुआ बजट है। जिससे पूरी उम्मीद है कि यह बजट प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के मिशन को पूरा करेगा। वहीं, इस केंद्रीय बजट में क्षेत्रीय असंतुलन को संतुलन में लाने की कोशिश की गई है, जो आगे भी जारी रखी जायेगी, ऐसे संकेत मिले हैं। क्योंकि देश के कुछ पिछड़े क्षेत्र हैं जिन्हें पिछली सरकारों ने नजरअंदाज किया है, इसलिए विकास की गंगा वहां तक पहुंचाना समावेशी विकास की सबसे बड़ी जरूरत है।

शायद इसी नजरिए से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए की गई विभिन्न घोषणाओं से पूर्वी भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इस लिहाज से बजट में 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक का पूंजीगत व्यय आवंटित किया गया है। केंद्रीय बजट में एक तरफ आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ रुपए और आगामी वर्षों में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की घोषणा की गई, जो अच्छी बात है। तो दूसरी तरफ बिहार को 26 हजार करोड़ रुपये देने का ऐलान किया गया है। ऐसा करके वित्त मंत्री ने अपने दोनों गठबंधन साथियों टीडीपी और जदयू को साधने की पहल की है, जो समझदारी भरा कदम है। इन दोनों राज्यों के आर्थिक हितों का ख्याल रखने से एनडीए सरकार पांच सालों तक चलती रहेगी और आगे के भी चुनावों में उम्दा प्रदर्शन करती रहेगी। इस आम बजट को युवाओं और महिलाओं के सपनों का बजट भी करार दिया गया है। क्योंकि इनके दृष्टिगत कौशल विकास और रोजगार सृजन की जो घोषणाएं हुई हैं, वह ऐतिहासिक हैं। इस प्रकार इस बजट में पीएम मोदी का विकसित भारत का सपना पूरी तरह से झलकता है। वहीं, अगर विपक्ष ने इस बजट की आलोचना की है तो इसका मतलब यह भी लगाया जा रहा है कि बजट अच्छा है, क्योंकि आलोचना करना तो उनका विपक्ष धर्म है। जिसका निर्वहन करने के लिए भी यह सरकार पूरे मौके देती है।

> इस आम बजट को युवाओं और महिलाओं के सपनों का बजट भी करार दिया गया है। क्योंकि इनके दृष्टिगत कौशल विकास और रोजगार सृजन की जो घोषणाएं हुई हैं, वह ऐतिहासिक हैं। इस प्रकार इस बजट में पीएम मोदी का विकसित भारत का सपना पूरी तरह से झलकता है।

इस बारे में एक तरफ सत्ताधारी टीडीपी कहती है कि वाईएसआर कांग्रेस के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी दिल्ली जाकर राज्य की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य के विकास और कल्याण को लेकर वित्तीय सहायता के लिए दो बार दिल्ली गए और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए 15000 करोड़ का विशेष पैकेज लेकर आए। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी इंडिया गठबंधन की राजद सांसद और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी कहती हैं कि राज्य में हत्या और चोरी हो रही है। मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिल रही है। युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही और किसानों की समस्या अभी भी जस की तस बरकरार है। ऐसे में बिहार को 26 हजार करोड़ रुपये आवंटित करना बिहार को झुनझुना देने के बराबर है।

सच कहूं तो पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक केंद्रीय बजट 2024 की आलोचना हो रही है। जहां पंजाब के संसद सदस्यों ने केंद्रीय बजट में धन आवंटन के मामले में उनके राज्य को अनदेखा करने का आरोप लगाया और विरोध प्रदर्शन तक किया। वहीं, महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने भी ताजा बजट में उनके राज्य की उपेक्षा करने का आरोप मढ़ते हुए संसद के बाहर प्रदर्शन तक किया। जबकि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहलाने का गौरव प्राप्त है। बजट में महाराष्ट्र को नजरअंदाज करना भाजपा को आगामी विधानसभा चुनाव में भारी पड़ सकती है, क्योंकि यहां की जनता ही असली सबक सिखाएगी। विपक्ष की इस राय में दम है कि पिछले दस वर्षों से मोदी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि हम सिर्फ नारे सुनते रहते हैं। आज के बजट में भी जुमले ही अधिक रहे। लिहाजा, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। न तो उन्हें सरकार चलाना आता है और न ही उन्हें लोगों के दर्द से कोई मतलब है। मौजूदा केंद्रीय बजट पर उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और पश्चिम बंगाल के नेताओं ने जिस तरह से नाखुशी दिखाई है, उस तरह से वैकल्पिक सुझाव नहीं दिए कि इसके बदलते क्या किया जाना चाहिए। यूपी की समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ठीक ही कहा कि सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। लेकिन टीम मोदी ने जो पिछले 10 वर्षों में बेरोजगारी बढ़ा दी है, उसके दृष्टिगत किये गए कोई ठोस उपाय नजर नहीं आते।

इस बजट में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी मोटा आवंटन होना चाहिए था, लेकिन बजट में कुछ भी नहीं किया गया है। किचन का ध्यान तक नहीं रखा गया है, क्योंकि सरकार मंहगाई के बारे में कोई कदम नहीं उठाना चाह रही है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने दो टूक कहा कि, अगर मुख्य बातें सामने आ गई तो सरकार की पोल खुल जाएगी। क्योंकि सरकार गलत है और दिखावा कर रही है। इस बजट में कुछ भी नहीं है और यह केवल गुमराह करने वाला है।

सीधा सवाल है कि उनको मुख्य बातें सामने लाने से रोक कौन रहा है। यदि कुछ होगा, तब तो लाएंगे। उनके लाने का इंतजार रहेगा, ताकि सरकार की पोल पट्टी खुले, यदि कुछ अंदरखाने चल रहा हो तो। मोदी सरकार का पुराना इतिहास बताता है कि ये 2 करोड़ रोजगार के वादे के साथ सत्ता में आई थी। लेकिन अब 10 साल बीत जाने के बाद चार करोड़ रोजगार पैदा करने की बात करती दिखाई पड़ी, जिसे लोग दोगुना झूठ समझते हैं। उनका तंज है, डबल इंजन की नरेंद्र मोदी की सरकार यानी डबल झूठ। इसका आशय स्पष्ट है कि यह कुर्सी बचाओ बजट है। जब पिछले दस वर्षों में बेरोजगारी दूर नहीं हुई तो अब कोई नई उम्मीद कैसे बांधी जा सकती है। हमलोग इस बारे में सिर्फ नारे सुनते रहे और आज भी बजट के जुमले ही ज्यादा मिले। लिहाजा, इस सरकार से किसी को कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि न तो उन्हें सरकार चलाने आता है और न ही उन्हें लोगों के दुःख-दर्द से कोई मतलब है। वे बजट बहुत कुछ बोलती हैं, लेकिन किसानों के लिए उन्होंने क्या किया? किसानों के लिए तीन कानून लाए गए, जिसे पूर्णतया वापस लेना चाहिए। इसका स्वरूप बदलकर कभी भी उसपर अमल नहीं किया जाना चाहिए।

इस बजट को जबरदस्त चालाकी भरा बजट भी करार दिया जा सकता है क्योंकि इसमें आम आदमी के सामने आने वाले मुद्दों के बारे में कुछ खास नहीं कहा गया। खासकर मनरेगा का कोई जिक्र नहीं किया गया। वहीं, आम व्यक्ति की आय में सुधार के लिए उठाए गए कदम भी अपर्याप्त हैं। जब बात गंभीर आय असमानता की आती है तो सरकार की ओर से इसे दूर करने वाले प्रयास भी बहुत कम देखने को मिलते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कुल मिलाकर यह बजट कांग्रेस के घोषणापत्र का कॉपी है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज युवा निधि योजना है। इसके तहत सरकार ने अप्रेंटिसशिप प्राप्त करने वाले प्रत्येक युवा को 5000 रुपये देने की घोषणा की है। इससे यह साबित होता है कि मोदी सरकार राहुल गांधी के विचारों को कॉपी कर रही है। यह खुशी की बात है। हालांकि, इस सरकार ने आंध्र प्रदेश व बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार कर दिया गया और दोनों राज्यों को विशेष पैकेज का लॉलीपॉप थमा दिया। इसलिए सियासी गलियारे में यह सवाल उठ रहा है कि, क्या निर्मला सीतारमण ने सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बजट पेश किया। या फिर यह महज बैसाखी के सहारे खड़ा रखने वाला बजट है। दरअसल, भाजपा नीत एनडीए सरकार को मालूम है कि अगर बजट बिहार और आंध्र प्रदेश के पक्ष में नहीं होता तो उनकी सरकार गिर जाती। लिहाजा, निर्मला सीतारमण ने भारत नहीं बल्कि एनडीए को फायदा पहुंचाने वाला बजट पेश किया है।

‘वह सभा ही नहीं है जिसमें वृद्ध न हों’

हिंदू धर्म और संस्कृति में वृद्ध जनों के सम्मान और सेवा संबंधी बड़ी-बड़ी बातें कही गई हैं। मनुस्मृति कहती कि 'अभिवादनशील और नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले की चार चीजें बढ़ जाती हैं: आयु, विद्या, यश और बल' । महाभारत में उल्लेख है कि 'वह सभा ही नहीं है, जिसमें वृद्ध न हों'

वाल्मीकि प्रसंग है कि रामायण में जब भरत श्रीराम को मनाने वन में गए हैं तो राम ने उनसे कुशल प्रश्न पूछने के बहाने सारी राजनीति सिखलाई है। श्रीराम उनसे सेवानिवृत्त पूछते हैं कि ₹तात ! क्या तुम देवतावों, पितरों, भृत्यों, पिता के समान आदरणीय वृद्धों, वैद्यों और ब्राह्मणों का सम्मान करते हो ? और अब तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा द्वारा भी 1 अक्टूबर का दिन 'अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के रूप में मनाने की अपेक्षा की गई है। वह मनाया भी जाता है। हालांकि सद्यः प्रस्तुत किए गए देश के आम बजट में वृद्धों की अवहेलना जारी है। वे बेचारे कुछ सुविधाओं के लिए आस लगाए बैठे थे, किंतु निराशा ही हाथ लगी। कुछ समय पहले तक उन्हें रेल किराए में छूट मिलती थी, जो मोदी सरकार ने खत्म कर दी थी। सोचा था अबकी शायद यह रियायत बहाल हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। चूंकि वृद्धजन युवाओं के समान पुरुषार्थ करने से तो रहे, अतः उन्हें डाकघर, बैंक आदि में जमा धन राशियों पर अधिक ब्याज मिलने की आशा रहती है। मोदी काल में ये दरें निरंतर घटीं। इससे उनका जेब खर्च कम का कम ही बना रहा। आयकर में उन्हें जैसी और जो अल्प सुविधा अब तक थी, वही बनी रही।

उससे आगे उन्हें शुक्ला कुछ भी नहीं मिल सका, पीसीएस जबकि महगाई बराबर बढ़ रही है। उनकी कर छूट सीमा अवश्य बढ़ाई जानी चाहिए थी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई। कोरोना काल में रोकी गई मंहगाई भत्ते की किश्त भी नहीं प्रदान की गई, जबकि कहा यह जा रहा है कि भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन चुका है। समाज में वृद्धों के साथ उपेक्षा और अत्याचार की खबरें आम हैं। संतानें उन्हें प्रताड़ित करती हैं, घर से निकाल देती हैं। इस पर जो कानून है, वह अव्यवहारिक है। फिलहाल केंद्र सरकार बुजुर्गों को रामभरोसे ही छोड़े है।

सत्ता के लिए खालिस्तान भी इनका माई बाप

निकट भविष्य में तैयार रहिए किसान आंदोलन और उपद्रव झेलने के लिए । अगर वर्तमान राजनीतिक माहौल की बात करें तो सरकार बनाने में नाकामयाब रही कांग्रेस अब खालिस्तान तक के समर्थन में उतर चुकी है। ब्राह्मण को जमकर कोसो, गाली दो और चुनाव में ओबीसी और दलित सहानुभूति से अपने स-ांसद विधायक बनाओ, राजनैतिक दलों का यह प्रमुख एजेंडा है जिसकी अगुवाई योजनाबद्ध ढंग से सपा और कांग्रेस कर रही है ।बात इंडी अलायन्स के बारे में की जाए तो राहुल और अखिलेश ही ऐसे दो नेता हैं जिनके हौसले यूपी में बुलंद हैं कारण बीजेपी कार्यकर्ताओ की बेरुखी ।यूपी की जीत से गदगद इन दोनों नेताओं की खुशियां छिपाए नहीं छिप रही क्यूंकि यूपी में भाजपा कार्यकर्ता हासिये पर रखें गए । उधर पंजाब के जालंधर से कांग्रेस सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने संसद में अलगाववादी आतंकी अमृतपाल सिंह के समर्थन में कहा, ₹पंजाब में 20 लाख लोगों द्वारा एक सांसद के रूप में चुना गया व्यक्ति एनएसए के तहत सलाखों के पीछे है। ये अघोषित आपातकाल है।₹ चन्नी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना हो रही है। लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि जिस अलगाववाद ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जान ले ली, कांग्रेस उसी अलगाववाद का समर्थन कैसे कर सकती है? वहीं, बीजेपी ने भी चरणजीत सिंह चन्नी के इस बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने सवाल करते हुए कहा, ₹कांग्रेस हमेशा अलगाववादियों और आतंकवादियों के पक्ष में क्यों बोलती है ? खुद देख लीजिए। वैसे अब गठबंधन के बाकी घटक कहीं दिखाई नहीं देते ।उनके नेता कोई खास बयानबाजी भी नहीं करते । सारा दारोमदारअपने कंधों पर उठाकर कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन का नेता भी चुपचाप कांग्रेस को बनाना चाहती है । कांग्रेस का मतलब राहुल है , सब जानते हैं । लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष वे बन ही गए हैं ।बाकी इंडी नेताओं का कोई खास रोल चार जून के बाद दिखाई नहीं दिया है । अखिलेश खुद को लाइम लाइट्स में रखकर साबित करना चाहते हैं कि गठबंधन को सम्मान दिलाने का श्रेय अकेले कांग्रेस का नहीं ।यह भी कि यूपी में कांग्रेस को जो मिला वह उनकी बदौलत मिला ।कांग्रेस का अपना वोट बैंक यूपी में नहीं है ।

इधर संसद न चलने देने की विपक्षी कोशिश कोई खास बात नहीं है ।यह काम विपक्षी दलों के जिम्में सदा रहा है ।फिर पिछले दस वर्षों की तो बात ही कुछ और है। इन सालों में एक नए रंग की राजनीति देखने को मिली। सत्ता चली जाने को कांग्रेस ने चूंकि राहुल सोनिया की जागीर लुट जाना समझा अतः वहीं होना था जो अब हो रहा है , दस साल से सब देख भी रहे हैं ।आगे जो लड़ाई होगी वह देखने लायक होगी ।

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने गुरुवार को बजट पर चर्चा के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में पंजाब को कुछ नहीं दिया गया। बीजेपी वाले हर रोज आपातकाल की बात करते हैं। आज देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति है।एक मशहूर नौजवान जो मशहूर सिंगर था उसको मार दिया गया। सिद्धू मूसेवाला के परिवार को इंसाफ नहीं मिला। यह भी आपातकाल है।

आपातकाल यह भी है कि 20 लाख लोगों की ओर से पंजाब में जिले लोकसभा का सदस्य चुना गया, वह एनएसए के तहत जेल में हैं। वह अपने क्षेत्र के लोगों की बात नहीं रख पा रहे हैं। विपक्ष के लोगों पर केंद्रीय एजेंसियां छोड़ दी जाती हैं उनको अंदर रखा जाता है। हजारों किसानों को खालिस्तानी कहा जाता है, यह भी आपातकाल है। अपनी समस्त ताकत दांव पर लगाने वाले इंडी गठबंधन का चरम संघर्ष था लोकसभा चुनाव ।आगे इतनी एकता नहीं बन पाएगी ।दूसरी ओर बीजेपी जितना खो सकती थी , खो चुकी है ।इस कांटे के संघर्ष से सबक लेकर बीजेपी पुनः कब तक फिर से खड़ी हो पाएगी इसका पता कुछ महीनों में लग जाएगा। निश्चित रूप से कैडर बेस पार्टी में फिर से उभरने का दम है ।लेकिन बीजेपी में नेतृत्व का प्रश्न हल करना अब उतना आसान नहीं है ।जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भी बीजेपी अभी तक नया अध्यक्ष नहीं खोज पाई ।आश्चर्य की बात है कि किसानों का आंदोलन उस राष्ट्रीय दिवस से प्रारंभ कराया जा रहा है जो तिरंगे की आन बान और शान का प्रतीक है ।बात साफ है कि अपच बड़ा भारी है , तमाम चूर्ण और नुस्खे नाकामयाब हो चुके हैं ।तो अब किसानों को आगे लाकर लम्बा खेलने की तैयारी है ।

पंकज कुमार मिश्रा,
जौनपुर यूपी

शिक्षा को कौशल विकास से जोड़ना होगा

> सामाजिक स्तर पर कहीं न कहीं यह संदेश देना होगा कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता और देश को सामान्य डिग्रीधारी युवाओं के मुकाबले हुनरमंद युवाओं की जरूरत अधिक है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि फिक्की-और सीआई आई जैसे संगठन यह कहते रहे हैं कि उन्हें जैसे कार्यकुशल युवा चाहिए वैसे नहीं मिल रहे हैं।

भले ही भाजपा ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए यह कहा हो कि वह रोजगार के मामले में लगातार झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं। भाजपा और साथ ही उसकी केन्द्र एवं राज्य सरकारों को इस झूठी धारणा के खिलाफ सक्रिय होना होगा कि रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। यह धारणा तथ्यों के विपरीत है। हाल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक अध्ययन में यह कहा गया कि मोदी सरकार के दस साल के शासन काल में मनमोहन सरकार की तुलना में कई गुना अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए। कुछ दिनों पहले रिजर्व बैंक ने एक विदेशी संस्था के आकलन को खारिज करते हुए यह बताया था कि पिछले वर्ष किस तरह 4.67 करोड़ नौकरियां बढ़ीं। रिजर्व बैंक के अनुसार, बीते वित्त वर्ष तक देश में कुल नौकरियां बढ़कर 64 करोड़ से अधिक हो गई हैं, जबकि उसके पिछले वर्ष उनकी संख्या करीब 60 करोड़ थी।

निजी क्षेत्र में रोजगार के और अधिक अवसर कै से पैदा हों, इसके लिए पक्ष-विपक्ष के राजनीतिक दलों को मिलकर कार्य करने की जरूरत है, लेकिन दुर्भाग्य से विपक्षी दलों ने यह माहौल बना रखा है कि रोजगार के अवसर पैदा करना केवल केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। चूंकि अपने देश में स्वरोजगार और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों के सही आंकड़े नहीं मिल पाते, इसलिए यह माहौल बनाने में आसानी होती है कि रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं बन रहे हैं। नौकरियों के मामले में यह धारणा हमारे समाज में भी व्याप्त है कि रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी होता है। विपक्षी दल भी यहमाहौल बनाते हैं और इसी कारण हर कोई सरकारी नौकरी की ताक में रहता है। इस सच को सभी को स्वीकारना होगा कि कोई भी सरकार हो, वह हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। इतनी सरकारी नौकरियां हें ही नहीं कि सभी को समाहित किया जा सके। सरकारी नौकरियों के प्रति आकर्षण का एक बड़ा कारण यह मान्यता भी है कि ये नौकरियां सुरक्षा की गारंटी और आरामतलबी का पर्याय होती हैं। कुछ तो बस इन्हें अतिरिक्त कमाई का साधन मानकर चलते हैं। चूंकि औसत सरकारी कर्मचारी जवाबदेही से मुक्त हैं और उनके कार्यों का मुश्किल से ही आकलन होता है, इसलिए वे अपने काम के प्रति वैसी लगन और प्रतिबद्धता नहीं दिखाते, जैसी आवश्यक है। यही कारण है कि उनकी उत्पादकता कम है और शायद इसी वजह से अब केन्द्र और राज्य सरकारों के अनेक विभाग आउटसोर्सिंग का सहारा लेने लगे हैं। अथवा अनुबंध पर नौकरियां देते हैं। इसका एक कारण औसत सरकारी कर्मचारियों में जवाब देही का अभाव भी है। यह किसी से छिपा नहीं क्योंकि अपने देश में यदि किसी को सरकारी नौकरी मिल जाती है तो वह तब भी चलती रहती है जब संबंधित व्यक्ति अपना काम सही तरीके से नहीं करता। यह सही समय है कि सरकारी नौकरियों को कार्यकुशलता एवं दक्षता की कसौटी पर कसा जाए। उचित यह होगा कि सरकारें ऐसी सेवा शर्तें बनाएं जिस-ासे सरकारी कम्रचारी जवाबदेह एवं जिम्मेदार बन सकें और जो यह मानकर चलते हैं कि ये नौकरियां आरामतलमी का पर्याय हें, उन्हें यह आभास हो सके कि सरकारी कर्मचारी के रूप में यदि वे अपना काम सही तरह नहीं करेंगे तो निजी क्षेत्र के कर्मियों की तरह उनकी भी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। ऐसा करके ही सरकारी नौकरियों के प्रति अनावश्यक चाहत को कम किया जा सकता है।

लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस मोदी सरकार के प्रति किस तरह हमलावर है, इसका प्रमाण पिछ्ले दिनों तब फिर मिला, जब राहुल गांधी ने गुजरात में नौकरी के लिए साक्षात्कार देने आए युवाओं की भीड़ का उल्लेख करते हुए कहा कि बेरोजगारी महामारी बन गई है और भाजपा शासित राज्य बेरोजगारी के गढ बन गए हैं। साफ है कि वह यह माहौल बनाना चाहते हैं कि रोजगार के मोर्चे पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में कोई चुनौती नहीं और सारी समस्या केन्द्र सरकार के स्तर पर और भाजपा शासित राज्यों में है। ऐसा कोई आकलन झूठ ही कहा जाएगा लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दल अब झूठ का भी सहारा ले रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले गोरखपुर में एक युवा की आत्महत्या पर भी विपक्षी नेताओं की ओर से यही झूठ फै लाया गया कि उसने नौकरी चली जाने के कारण आत्महत्या कर ली, जबकि उसने पारिवारिक कारणों से नौकरी छोड़ी थी।

यह सही हे कि रोजगार के और अधिक अवसर पैदा करने की आवश्यकता है लेकिन इस आवश्यकता की पूर्ति करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं। इसकी पूर्ति तो केन्द्र और राज्यों, दोनों को मिलकर करनी होगी। इसके लिए दोनों को निजी क्षेत्र का सहयोग लेना और देना होगा। उन्हें यह देखना होगा कि वे कौन से क्षेत्र हैं जहां रोजगार के अधिक अवसर पैदा हो सकते हैं। निजी क्षेत्र में रोजगार के अधिकाधिक अवसर पैदा करके ही सरकारी नौकरियों के आकर्षण को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि युवाओं में कौशल विकास कियाजाए। इसकी आवश्यकता इस लिए है क्योंकि आज हुनर वाले कार्यों की जरूरत बढ़ गई है। अपने देश में ऐसे डिग्रीधारी युवाओं की संख्या बढ़ रही है, जिनके पास किसी तरह का हुनर नहीं और जिनकी शिक्षा-दीक्षा का स्तर ऐसा है कि उनमें से अनेक तो ढंग से एक आवेदन पत्र भी नहीं लिख सकते। एक समस्या यह भी है कि हुनर वाले अनेक कार्यों को या तो छोटा काम समझा जाता है या उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता है। इसी कारण कई उद्योग धंधों को जैसे हुरनमंद युवाओं की आवश्यकता है, वैसे उन्हें नहीं मिल पाते। स्पष्ट है कि- सामाजिक स्तर पर कहीं न कहीं यह संदेश देना होगा कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता और देश को सामान्य डिग्रीधारी युवाओं के मुकाबले हुनरमंद युवाओं की जरूरत अधिक है। इस-ाकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि फिक्की-और सीआई आई जैसे संगठन यह कहते रहे हैं कि उन्हें जैसे कार्यकुशल युवा चाहिए वैसे नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि शिक्षा को कौशल विकास से जोड़ना होगा।

7 वें बजट के मुख्य तथ्य

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार, 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। यह उनका लगातार सातवां बजट होगा, जो पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देगा।

केंद्रीय बजट 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार, 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। यह उनका लगातार सातवां बजट होगा, जो पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देगा।

इस साल दो बजट पेश किए जाएंगेः फरवरी में एक अंतरिम बजट और इस महीने एक पूर्ण बजट। यह व्यवस्था इस तथ्य के कारण है कि आम चुनावों से ठीक पहले पूर्ण बजट पेश नहीं किया जा सकता है। 23 जुलाई को पेश किया जाने वाला बजट पिछले महीने फिर से चुनाव जीतने के बाद भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का पहला बजट होगा।

केंद्रीय बजट में दो मुख्य घटक होते हैं: वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसमें सरकारी राजस्व का विवरण होता है, और अनुदान की मांग, जिसमें अनुमानित व्यय की रूपरेखा होती है।

भारत का पहला बजट 7 अप्रैल, 1860 को ईस्ट इंडिया कंपनी के स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था। इसने आयकर की शुरूआत की, जो आज एक महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत है।

स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर, 1947 को देश के पहले वित्त मंत्री आरके षणमुखम चेट्टी द्वारा पेश किया गया था।

पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड है, जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कुल 10 बजट पेश किए थे।

निर्मला सीतारमण के नाम सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड है, जो 1 फरवरी, 2020 को दो घंटे और 40 मिनट तक चला। उन्हें दो पेज शेष रहने पर अपना भाषण छोटा करना पड़ा।

वित्त मंत्री ने पेश किया मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट 2024-2025

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गत दिनों 23 जुलाई को मोदी 3.0 का पहला बजट पेश कर रहीं हैं। इस बजट से आम जनता से लेकर उद्योग जगत को बड़ी उम्मीदें हैं। इस बजट में सरकार का फोकस महिलाओं,युवाओं पर रहा है। वहीं, बिहार और आंध्र प्रदेश के विकास पर मोदी सरकार का खास ध्यान रहा है। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए हैं।

बजट के बाद इन चीजों के घटेंगे दाम : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैंसर मरीजों को इलाज में बड़ी राहत दी है। मेडिकल में कैंसर से जुड़ी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं, उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है।

इससे कैंसर का इलाज सस्ता होगा : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में करदाताओं के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि न्यू टैक्स रिजीम को 75000 रुपये कर दिया है। पहले स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन 50,000 रुपये था।

बिहार में बहार है, एनडीए सरकार हैः बजट 2024 के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, यह बजट संतुलित है, जिसके चार स्तंभ हैं- महिला, युवा, किसान और गरीब। बिहार में बहार है, एनडीए की सरकार है। बिहार को सुपर पैकेज दिया गया है।

3 लाख तक की कमाई में कोई टैक्स नहीं : इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए गए हैं। नई टैक्स रेजीम में 0 से लेकर 3 लाख तक में कोई टैक्स नहीं। नई कर व्यवस्था में तीन लाख तक कर मुक्त किया गया। नौकरीपेशा को राहत, 3 लाख तक की आय कर मुक्त, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार से बढ़कर 75हजार रुपए किया गया।

रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा दिया जाएगाः बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए 10 लाख करोड़ का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं, रेंटल हाउसिंग रेगुलेशन के लिए नियम बनाएंगे। स्टाम्प ड्यूटी कम करने वाले राज्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। एनर्जी ट्रांजिशन के लिए नई नीति लाई जाएगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैंसर मरीजों को इलाज में बड़ी राहत दी है। मेडिकल में कैंसर से जुड़ी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं, उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। इससे कैंसर का इलाज सस्ता होगा।

वित्त मंत्री ने महिलाओं को भी बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6 फीसदी कर दी है। इससे सोने और चांदी से बनने वाले गहने सस्ते हो जाएंगे। यह आभूषण के शौकीनों के लिए बड़ी राहत होगी, क्योंकि सोने और चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। वित्त मंत्री ने कुछ टेलिकॉम इक्विपमेंट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया है। पहले इन प्रोडक्ट्स पर 10 फीसदी बेसिक कस्टम ड्यूटी थी, लेकिन अब 15 फीसदी लगेगी। सरकार ने प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है। इसका मतलब है कि प्लास्टिक से बनी चीजों के दाम भी बजट के बाद बढ़ सकते हैं।

बिहार में महाबोधि और विष्णुपद कॉरिडोर का होगा विकास : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पर्यटन हमेशा से हमारी सभ्यता का हिस्सा रहा है। भारत को वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करने के हमारे प्रयासों से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और अन्य क्षेत्रों में भी अवसर खुलेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि मैं प्रस्ताव करती हूं कि गया में विष्णुपथ मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर का आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। हम उन्हें विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने के लिए सफल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर वहां कॉरिडोर विकसित करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में राजगीर और नालंदा के लिए एक व्यापक विकास पहल की जाएगी। हम ओडिशा में पर्यटन को बढ़ावा देंगे, जिसमें प्राकृतिक सुंदरता, मंदिर, शिल्पकला, प्राकृतिक परिदृश्य, वन्यजीव अभयारण्य और प्राचीन समुद्र तट हैं।

डेट रिकवरी के लिए ट्रिब्यूनल्स खोलने जाएंगे : वित्त मंत्री ने बताया कि आईबीसी के तहत और एनसीएलटी ट्रिब्यूनल खोले जाएंगे। सरकार डेट रिकवरी के लिए ट्रिब्यूनल्स खोलने जा रही है। इसके अलावा देश में डिजिटल पब्लिक इंफ्रा एप्लीकेशन विकसित किए जाएंगे।

युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेगी सरकार: केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा,सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी, जिसमें इंटर्नशिप भत्ते के रूप में 5000 रुपये प्रति माह और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता होगी। रोजगार व कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी पांच योजनाओं के लिए दो लाख करोड़। 500 टॉप कंपनियों में पांच करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का प्रावधान। पहली जॉब ज्वाइन करने वालों के 15 हजार की तीन किश्त सीधे ईपीएफओ एकाउंट में। केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25हजार छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे लोन राशि के 3 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे।

बजट से बिहार को मिली यह सौगात : वित्त मंत्री ने बताया कि बिहार में अब सड़क, बिजली और रेलमार्ग का जाल बिछाया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया कि बिहार में नए मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट बनेंगे। इसी के साथ वैशाली-बोधगया एक्सप्रेस-वे को भी मंजूरी मिल गई है। बिहार में 26हजार करोड़ से सड़कों का जाल बिछाया जाएगा।

निर्मला सीतारमण ने बताया कि पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे को मंजूरी दे दी गई है। बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावॉट का पावर प्रोजेक्ट भी स्थापित किया जाएगा। इसी के साथ केंद्र सरकार गंगा पर दो नए ब्रिज भी बनाएगी।

आंध्र प्रदेश के लिए सरकार का खास प्लान : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ₹आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम- हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं।

राज्य की पूंजी की आवश्यकता को समझते हुए हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी।

मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव : केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे। महिलाओं और लड़कियों के लिए मोदी सरकार का बड़ा एलान : महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी।

बिहार समेत इन राज्यों के लिए सरकार बनाएगी पूर्वोदय योजना : पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए सरकार पूर्वोदय योजना बनाई जाएगी। पूर्वोदय स्कीम में बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश शामिल।

ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए : पहली नौकरी वालों के लिए एक लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी। नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी लाने वाली है सरकार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कृषि और सहायक सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ का ऐलान किया जा रहा है। सरकार नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी लाने वाली है। वहीं, सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार क्लस्टर स्कीम लाएगी। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार एवं कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, विनिर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा संरक्षण, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, नई पीढ़ी के सुधार।

रोजगार और कौशल पर मोदी सरकार का ध्यान: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

चार अलग-अलग जातियों पर मोदी सरकार का ध्यानः केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा,जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, हमें 4 अलग-अलग जातियों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि किसानों के लिए हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की है, जो लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मार्जिन के वादे को पूरा करते हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए।

लोकसभा में बजट पेश कर रहीं वित्त मंत्री : लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने बजट पेश करते हुए कहा कि देशवासियों को मोदी सरकार पर भरोसा है।

सेवामुक्त अग्निवीर जवानों को आरक्षण: सांत्वना देने जैसा ही

वर्ष 2022 में केंद्र सरकार ने पहली बार पूर्व की भांति नियमित भर्ती के बजाय भारतीय सेना के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की थी। जिसमें साढ़े 17 साल से लेकर 21 साल की उम्र के युवाओं को चार साल के लिए सेना में भर्ती करने का प्रावधान किया गया है। इनमें से सिर्फ 25 प्रतिशत को ही अगले 15 वर्ष के लिए सेना में रखा जाना है। शेष 75 फीसदी अग्निवीर सेवा से बाहर कर दिए जायेंगे।

प्रधानमंत्री से लेकर बल इंजन सरकार के मुख्यमंत्रियों तक अग्निवीर को लेकर यही कहा जाता रहा है कि अग्निवीर योजना बहुत अच्छी योजना है। इसे लेकर युवाओं में बहुत उत्साह है। विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अग्निवीर जब अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस सेवा और पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा देगी. उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। जहां तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अन्य भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों का प्रश्न है यदि अग्निवीर योजना बहुत अच्छी योजना है तो इन प्रदेशों को केन्द्र सरकार की नीतियों का समर्थन देने के लिए अलग से आरक्षण देने की घोषणा करने की जरूरत ही क्यों आ पड़ी? पूरे देश में आउटसोर्सिंग चल रही है। नियमित रिक्त पदों को भरने के बजाय उन्हें वर्कफोर्स कम्पनियों द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले मानव श्रम को सरकारी महकमें में भर्ती किया जा रहा है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि सरकारी सेवा भी एक तरह से ठेके पर चली गई है। बहुत से सरकारी महकमे में बिना किसी नियुक्ति या अधिकार के अदालतों से लेकर तहसीलों तक में निजी तौर पर लोग फाइलें सम्भाल रहे हैं और उससे अच्छी खासी कमाई करने में लगे हुए हैं। क्योंकि न तो उनकी कोई जवाबदेही है और न ही कोई जिम्मेदारी। रिपोर्ट तो यहां तक आ रही है कि लेखपालों तक ने ऐसे सहायक रख लिए हैं जिन्हें सरकार की ओर से कोई पैसा नहीं मिलता है वह जनता से वसूल कर रहे हैं और अनधिकृत तौर पर बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सेना में भर्ती हुए अग्निवीरों को सेना की चार साल की सेवा करके आने के बाद प्रदेश में आरक्षण देने की घोषणा की है कि ऐसे अग्निवीरों को पीएसी और पुलिस में आरक्षण दिया जायेगा। राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ जो भाजपा शासित राज्य हैं, ने भी सेवामुक्त अग्निवीर जवानों को आरक्षण और अपने राज्य में उन्हें आरक्षण देने की घोषणा की है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में 10 प्रतिशत पद आरक्षित करने का फैसला किया था।

जहां तक विभिन्न डबल इंजन सरकारों द्वारा अग्निवीरों को आरक्षण दिये जाने का प्रश्न है यदि विपक्ष ने लोकसभा चुनाव के दौरान इसे मुद्दा न बनाया होता तो यह भी घोषणाएं न हुई होतीं। चूंकि विपक्षी दलों ने यह घोषणा चुनाव के दौरान की थी कि उनकी सरकार आयेगी तो 24 घंटे में अग्निवीर योजना को समाप्त कर देगी, इन कारणों से अब भाजपा शासित राज्य की सरकारें एक-एक करके अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा अपने राज्यों में कर रही हैं। दुर्भाग्य है कि देश के अन्दर एक ही तरह का कार्य करने वालों के लिए अलग-अलग वेतनमान, सुविधाएं और सम्मान की स्थिति है। सेना के लिए इस प्रकार का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह अन्य विभागों और कार्यों से भिन्न प्रकृति का तथा जोखिम का उच्चस्तर है।

अग्निवीरों के लिए राज्यों में आरक्षण की घोषणा करके न तो उनका सेना की भांति समायोजन हो सकता है और न ही वेतन भत्ते सुविधाएं और सम्मान ही हासिल हो सकता है। जहां तक आरक्षण दिये जाने का प्रश्न है यह तो तभी सम्भव हो पायेगा जब जहां आरक्षण दिया जाना है वहां के लिए स्थान रिक्त हों और उन पदों पर भर्ती भी 'होनी हो। कुल मिलाकर यह एक सान्त्वना देने जैसा ही है।

जहां तक नौकरियों में या सरकारी सेवा में आरक्षण या प्राथमिकता का प्रश्न है यह तो तब उठेगा जब नौकरियां बची होंगी जिसके लिए है जगहें निकाली जायेंगी तभी उन्हें आरक्षण भी दिया जा सकेगा। यदि नौकरियों में नियुक्तियां ही नहीं होंगी तो आरक्षण लोगों को कहां मिल सकेगा वह चाहे ओबीसी हो एससीएसटी दिव्यांग आर्थिक कमजोर वर्ग से या फिर अग्निवीर ही क्यों न हो। सेना के अपने नियम कायदे और सुविधाएं तथा सम्मान होते हैं। सेना में होने वाली भर्तियों में अधिकांशतः किसान और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ही जाते हैं। सेना के बड़े अधिकारी पदों के लिए ही एनडीए के माध्यम से लोग जाते हैं।

जिस प्रकार बेरोजगारी का हाल है उसमें जब स्वीगी जोमैटो जैसी कम्पनियों में अल्पआय और पार्सल पहुंचाने के लिए लोग अपना वाहन मोबाइल लेकर नौकरी कर रहे हैं तो अग्निवीर के चार साल की भर्ती के लिए भी लोगों की भीड़ की कमी थोड़े ही पड़ेगी। लोग आयेंगे ही भले ही उन्हें चार साल की सेवा का अवसर क्यों न मिले। यह सही है कि आज के युग में युद्ध में आमने-सामने की सीधी लड़ाई के बजाय संचार, तकनीक और मशीनों का उपयोग बढ़ गया है जिसमें बैठा व्यक्ति भी दूसरे देश को अपनी तकनीकी क्षमता के जरिए क्षति पहुंचा सकता है।

अखिलेश यादव ने किया बजट के खिलाफ प्रदर्शन

केंद्रीय बजट में भेदभाव के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने संसद में किया प्रदर्शन

खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके और वामपंथी दलों के कई सांसद संसद के मकर द्वार की सीढ़ियों पर आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।

नई दिल्ली। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय बजट 2024 में भेदभाव का आरोप लगाते हुए संसद परिसर के अंदर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने केंद्रीय बजट में विपक्ष शासित राज्यों के साथ कथित भेदभाव को लेकर बुधवार को संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके और वामपंथी दलों के कई सांसद संसद के मकर द्वार की सीढ़ियों पर आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। बजट का विरोध करते हुए खड़गे ने कहा, ₹यह बजट जनविरोधी है, किसी को न्याय नहीं मिला है। उन्होंने विशेष पैकेज की बात की है, लेकिन विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। यह लोगों के साथ धोखा करने वाला और अन्यायपूर्ण बजट है। सांसदों ने 'हमें भारत का बजट चाहिए, एनडीए का नहीं' और 'एनडीए ने बजट में भारत को धोखा दिया' जैसे पोस्टर उठाए हुए थे। कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने कहा, ह्यह्यकल बजट के माध्यम से भारत सरकार ने संघीय व्यवस्था को कायम रखने के सभी सिद्धांतों का उल्लंघन किया।उन्होंने कहा, ₹बजट का उद्देश्य सरकार को बचाना था। सिर्फ दो राज्यों को इतनी सारी रियायतें देना। हम आंध्र प्रदेश और बिहार को फंड देने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अन्य राज्यों को भी न्याय मिलना चाहिए। इसीलिए हम आज आंदोलन कर रहे हैं। यहां तक कि लोग भी इससे नाराज हैं। सपा सांसद जया बच्चन ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि युवाओं से झूठे वादे किए गए हैं।

मार्क्सवादी आलोचना से खासे प्रभावित रहे नामवर सिंह

नामवर सिंह ने लेखन, अध्यापन, व्याख्यान के अलावा जनयुग और आलोचना जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। साल 1959 में उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश के चंदौली से लोकसभा चुनाव लड़ा। लंबे समय तक प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष रहे। नामवर सिंह की प्रतिभा का उनके समकालीन भी लोहा मानते थे। बाबा नागाजुन उन्हें चलता फिरता विद्यापीठ कहते थे तो विश्वनाथ त्रिपाठी उन्हें अज्ञेय के बाद हिन्दी का सबसे बड़ा स्टेट्समैन मानते थे। एक नामवर और अनेक विश्लेषण हर एक के अपने नामवर, नामवर सिह आखिरी दम तक हिन्दी साहित्य की सेवा करते रहे। उनके जाने से हिन्दी आलोचना का एक युग समाप्त हो गया।

नामवर सिंह हिन्दी साहित्य में अकेले ऐसे साहित्यकार थे, जिनके जीतेजी वर्ष 2001 में सरकारी स्तर पर देश के 15 अलग-अलग स्थानों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, भोपाल, लखनऊ, बनारस, आदि में उन पर एकाग्र कार्यक्रम 'नामवर निमित्त' आयोजित हुए जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी की। नामवर सिंह तकरीबन छह दशक तक हिन्दी साहित्य में आलोचना के पर्याय रहे।

डॉ. रामविलास शर्मा के बाद हिन्दी में वे प्रगतिशील आलोचना के आधार स्तंभ थे। इस मुकाम पर नामवर सिंह ऐसे ही नहीं पहुंच गए थे, बल्कि इसके लिए उन्होंने बड़े जतन किए थे। आलोचना विधा को अच्छी तरह से साधने के लिए उन्होंने खूब अध्ययन, मनन किया। देशी विद्वानों के साथ-साथ विदेशी विचारकों को जमकर पढ़ा और खासतौर से वे मार्क्सवादी आलोचना से बेहद प्रभावित थे।

एक साक्षात्कार के दौरान उनकी यह स्वीकारोक्ति रही कि 'यदि हिन्दी में रामचंद शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, की आलोचना मेरे लिए एक परम्परा की अहमियत रखती है, तो दूसरी परम्परा पश्चिम की, लगभग एक सदी में विकसित होने वाली मार्क्सवादी आलोचना है, जो मेरा अमूल्य रिक्थ (विरासत) है। इसमें मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन के अलावा सबसे उल्लेखनीय नाम ग्राम्शी, लूकांच, वाल्टर बेंजामिन के हैं।'

आज मार्क्सवादी आलोचना पर खूब वार्ताएं की जाती हैं। हिन्दी साहित्य में मार्क्सवादी आलोचना को स्थापित करने का श्रेय यदि किसी अकेले को दिया जाता है तो वह हैं नामवर सिंह। साहित्य पत्रिका 'वसुधा' के नामवर सिंह पर केन्द्रित अंक में प्रसिद्ध कथाकार भीष्म साहनी ने नामवर सिंह की अहमियत को बयां करते हुए अपने एक लेख 'दुश्मन के बिना' में लिखा था, 'मार्क्सवाद कोई रामनामी दुपट्टा नहीं है, जिसे ओढ़ लिया, या ऐसे कोई सूत्र नहीं है जिन्हें कंठस्थ कर लिया तो मार्क्सवादी आलोचक बन गए। मार्क्सवाद एक दृष्टि है, जिसका प्रयास जीवन के यथार्थ को एकांगिता में न देखकर समग्रता में, व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने का है, जो व्यक्तिनिष्ठ न होकर वस्तुनिष्ठ होती है। इस मार्ग पर बहुत लोग नहीं चले हैं, और जो लोग चले हैं, उनका रास्ता भी आसान नहीं रहा। इस रास्ते पर चलते हुए तथाकथित विसंगतियों और भटकावों का महत्व नहीं है। महत्व उस सतत प्रयास का है जो पूर्वाग्रहों और संस्कारों से मुक्त, साहित्य में लक्षित होने वाले अपने काल के यथार्थ को समझने और परखने में लगा है और अकेले ही सही, नामवर जी इस रास्ते पर खूब चले हैं और चलते जा रहे हैं।'

हिन्दी साहित्य के आकाश में नामवर सिंह उन नक्षत्रों में से एक है, जो अपनी चमक हमेशा बिखेरते रहेंगे। उनकी चमक कभी खत्म नहीं होगी। नामवर की विद्वता कोई सानी नहीं था। साहित्य, संस्कृति, राजनीति और समाज कोई सा भी विषय हो, वे धाराप्रवाह बोलते थे। उनको सुनने वाले श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। हिन्दी साहित्य में उनका स्टार जैसा मर्तबा था। कुछ लोग जो जिन्दगी भर नामवर सिंह के विचारों से असहमत रहे और उनकी आलोचना करते रहे, वे भी अब आज किसी न किसी बहाने उन्हें याद करते हैं। आलोचना, आरोप और विरोध की तो नामवर सिंह ने जीवन भर परवाह नहीं की।

श्रीनरायण पाण्डेय को लिखे एक पत्र में उन्होंने लिखा था, 'आरोप करने वालों को करने दें, क्योंकि जिनके पास कुछ नहीं होता, वही दूसरों पर आरोप करता है। अपनी ओर से आप अधिक वही कर सकते हैं कि आरोपों को ओढें नहीं, बिछाने की चीज है-वह चादर नहीं, दरी है। ठाठ से उस पर बैठिए और अचल रहिए।'

नामवर सिंह ने अपनी जिन्दी में विपुल साहित्य रचा। हिन्दी साहित्य में नित्य नए प्रतिमान स्थापित किए। 'नई कहानी' आंदोलन को आगे बढ़ाने का भी उन्हें ही श्रेय जाता है। 'हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योगदान', 'कविता के नए प्रतिमान', 'छायावाद', 'दूसरी परंपरा की खोज', 'इतिहास और आलोचना', 'कहानी : नई कहानी', 'वाद-विवाद-संवाद', 'आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां', 'बकलम खुद', 'प्रेमचंद और भारतीय समाज' आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं।

कहानीः नई कहानी किताब में जहां नामवर सिंह ने नई कहानी से संबंधित सैद्धांतिक सवालों की पड़ताल की है, तो कविता के नए प्रतिमान में वे नई कविता के काव्य सिद्धांतों का व्यापक विश्लेषण करते हैं। कहा जा सकता है कि हिन्दी साहित्य में एक नई आधार भूमि तैयार करने में नामवर सिंह का बड़ा योगदान है। उनकी शुरुआती रचनाएं एक आवेग में लिखी गई हैं। बकौल नामवर सिंह- 'छायावाद पुस्तक मैंने कुल दस दिन में लिखी। कविता के नए प्रतिमान इक्कीस दिन में दूसरी परम्परा की खोज दस दिन में लिखी गई है। इस बात से सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक समय लिखने का उनमें किस तरह का जबरदस्त माद्दा था। यह बात अलग है कि अध्यापकीय एवं प्रगतिशील लेखक संघ की सांगठिनिक जिम्मेदारियों और दीगर साहित्यिक, सांस्कृतिक मसरूफियतों के चलते वे आगे ज्यादा नहीं लिख सके। वरना उनकी और भी कई किताबें होतीं।

अपनीजिंदगी के आखिरी दो-तीन दशकों मेंहालांकि नामवर सिंह ने कुछ नया नहीं लिखा था, लेकिन देश के अलग-अलग हिस्सों में वेजहां जाते और वक्तव्य देते थे, वे वक्तच्य भी लिपिबद्ध हो गए। बीते कुछ सालों में उनकी जो नई किताबें आईं, वे इन्हीं वक्तव्यों का संकलन हैं।

कहा जा सकता है कि देश की वाचिक परम्परा को आगेबढ़ाने में भी उनका बड़ा योगदान है। एक साक्षात्कार में उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि व्याख्यान के सिलसिले में वे इस पूरे महादेश को तीन बार नाप चुके हैं। अपने आखिरी समय में नामवर सिंह का मन लिखे से ज्यादा भाषण में रमता था। वाचिक परम्रा की अहमियत बताते हुए उन्होंने खुद एक जगह पर कहा था कि जिस समाज में साक्षरता पचास फीसदी से कम हो, वहां वाचिक परम्परा के द्वारा ही महत्वपूर्ण काम किया जा सकता है। मेरी आलोचना को, मेरे बोले हुए को, मौखिक आलोचना को आप लोक साहित्य मान लीजिए। साहित्य में नामवर सिह कीदीर्घ साधना के लिए उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान मिले, जिसमें कविता के नए प्रतिमान किताब के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कारभी शामिल है। सच बात तो यह हे कि उनका कद कई पुरस्कारों और सम्मानों से बड़ा था। वे जिसे छू देते, वह कुंदन बन जाता था।

नामवर सिंह ता-उम्र धर्म निरपेक्षता के पक्षधर रहे। उन्होंने अनेक मर्तबा हिन्दी में साम्प्रदायिक विरोधी साहित्यिक मोर्चे की अगुआई की। वे हिन्दी के तो विद्वान थे ही उर्दू, अंग्रेजी एवं संस्कृत भाषा पर भी उनकी अच्छी पकड़ थी। कोई भी व्याख्यान देने से पहले वे गंभीर एकेडमिक तैयारी करते थे। इसके लिए छोटे-छोटे नोट्स बनाते और जब मंच पर व्याख्यान देने के लिए खड़े होते, तो पूरे सभागार में एक समा बंध जाता लोग डूबकर उन्हें सुनते।

देशहित में नहीं फ्री में उड़ाना

तीन सौ यूनिट बिजली फ्री
देने का जो किया था वायदा
सत्ता जब मिल गई झूठ से
तब एक सौ पच्चीस भी लग रही ज्यादा

लोगों को झूठ के जाल में फंसाना
नेताओं का काम है यह पुराना
झूठ पर झूठ लगातार बोलना
हर बार लोगों को मूर्ख बनाना

बन्द करो अब मूर्ख बनाना
लोगों को अब लगा है समझ आना
वायदा क्यों करते हो ऐसा
जो मुश्किल पड़े फिर निभाना

देर से ही सही यह फैसला है अच्छा
बन्द करो अब घर बैठ कर किसी को खिलाना
सरकार तो बन जाती है ऐसे फैसलों से
लेकिन देश हित में नहीं है लोगों का पैसा उड़ाना

फ्री की सुविधाओं ने देश को पंगु बना दिया
जहां देखो सब्सिडी में पैसा उड़ा रहे
राशन जो फ्री में मिल रहा बेचा जा रहा
फिर भी लगातार उनको दिए जा रहे

रवींद्र कुमार शर्मा
घुमारवीं
जिला बिलासपुर हि प्र

अखिल भारतीय साहित्य परिषद ने गुरु पूर्णिमा पर काव्य गोष्ठी का किया आयोजन

भवानीमंडी अखिल भारतीय साहित्य परिषद राजस्थान इकाई भवानीमंडी द्वारा गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर लालचंद आदर्श विद्या मंदिर में शनिवार को काव्य गोष्ठी आयोजित की ।परिषद के अध्यक्ष डॉ. राजेश पुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि काव्य गोष्ठी में मुख्य अतिथि प्रकाश चन्द्र सोनी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी झालावाड़ विशिष्ट अतिथि शिक्षाविद गंगास्वरूप द्विवेदी पूर्व उप निदेशक शिक्षा विभाग श्रीमती उमारानी द्विवेदी कमल सुरेका रामस्वरूप शर्मा प्रधानाचार्य लालचंद आदर्श विद्या मंदिर भवानीमंडी हरगोपाल माहेश्वरी विद्यालय संचालक मोहनलाल वर्मा महामंत्री झालावाड़ इकाई रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेश निगम जी झालावाड़ इकाई अध्यक्ष ने की।

कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने माँ सरस्वती के पूजन अर्चन व दीप प्रज्वलन कर किया।

काव्य गोष्ठी में रचनाकारों ने गुरु पूर्णिमा पर आधारित गीत दोहे आदि छंदबद्ध व छंदमुक्त कविताएँ सुनाई। इस दौरान काव्य गोष्ठी में काव्य पाठ डॉ. राजेश कुमार शर्मा पुरोहित अरुण कुमार गर्ग हिमांशु चतुवेर्दी राजेन्द्र आचार्य राजन महावीर प्रसाद जैन दर्शन सिंह अमनदीप सिंह नवीन श्रीवास्तव आशारानी जैन आशु सुनेल बाल कवयित्री शुभांगी शर्मा आकांशा राठौर श्रद्धा तिलवाडिया डॉ.अनिल गुप्ता निर्मल औदीच्य सुनील राठौर भेरूलाल नागर नखराला डॉ. शिवशंकर सोनी संजय श्रीमाल भवानीशंकर वर्मा झालावाड़ भीकम सिंह ,आर्मित सिंह अशोक सुमन ने किया।

काव्य गोष्ठी का श्रीगणेश डॉ. राजेश कुमार शर्मा पुरोहित के स्वागत भाषण से किया गया।

सभी उपस्थित रचनाकारों का स्वागत परिषद द्वारा किया गया। काव्य गोष्ठी का शानदार संचालन कवि अरुण कुमार गर्ग ने किया। गिरधर गोपाल शर्मा किशोर राठौर महेश चौकसे डॉ विष्णु सेन की गरिमामय उपस्थिति रही।

जेलों में जातिगत भेदभाव गंभीर समस्या

जातिगत भेदभाव आज भी एक बहुत बड़ी समस्या है यहीं कारण है कि लोगों को आज भी न्याय नहीं मिल पाता है और न ही सामाजिक आर्थिक तौर पर उन्हें बराबरी ही हासिल हो पाती है। मानवाधिकार कानून और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को लिखने वाली पत्रकार सुकन्या शांता ने इस प्रकार के मुद्दों को उठाया है जिसके फलस्वरूप यह सुनवाई हो रही है। पत्रकार शांता ने भारत के 17 राज्यों के लिए जेलों में जाति के आधार पर काम के विभाजन पर आधारित एक रिसर्च किया और उसकी रिपोर्ट तैयार की थी। जिसमें कहा गया कि जेलों में जाति के अनुसार, काम का विभाजन किया जाता है अगर कोई नाई होगा तो जेल में उसे बाल और दाढ़ी बनाने का काम मिलेगा, ब्राह्मण कैदी खाना बनाते हैं और वाल्मीकि समाज के कैदी सफाई करते हैं। संविधान ने नागरिकों को बराबरी का अधिकार दिया है लेकिन समाज में अभी भी स्थिति में बहुत बदलाव नहीं आया है क्योंकि यह बदलाव सामाजिक सुधार के माध्यम से आता है जो फिलहाल हो नहीं रहा है और सामंतवादी व्यवस्था का अभी भी अंग बना हुआ है जिसके दर्शन कभी मिड डे मील में दलित जातियों की रसोइयों के बनाये खाने के बहिष्कार के तौर पर दिखाई देता पड़ता है तो कभी कोई किसी दलित के सिर पर पेशाब कर देता है।

कहीं ऐसे लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने किसी को छू लिया है या कुछ उठा लिया है या किसी बड़े घर के कुंए या नल का पानी पी लिया है। यदि सेवा में भी ऐसी जातियों के लोग हैं जिन्हें वर्ण व्यवस्था में निचले स्तर का माना जाता रहा है तो सरकारी सेवाओं में आने के बाद भी उनके साथ एक कर्मचारी की भांति नहीं बल्कि उसके जातीय आधार पर उसके साथ व्यवहार होता है। स्कूल कालेजों में भी यह स्थितियां दिखाई देती हैं। यह तो सामाजिक स्थितियों की बातें हैं लेकिन यदि सरकारी तौर पर भी जेलों में भी यही सब कुछ हो रहा है जहां

सुकन्या शांता ने दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में जनहित की इस आशय की याचिका दायर की थी कि जेलों में जातिगत भेदभाव होता है।

हर एक चीज के नियम हैं कि बंदी सजायाफ्ता राजनैतिक बंदी के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जायेगा। लेकिन यदि हमारे जेल मैनुअल भी जातिगत भेदभाव के शिकार है तो पहले उन नियमों को भी बदलना होगा जो संविधान की मूल भावना के विपरीत हैं। अंग्रेजो के समय में तो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की जातियों को अपराधशील जातियों की श्रेणी में रखा गया था। अंग्रेजों के समय बने जेल मैनुअल बीते दिनों की बातें हो सकती हैं लेकिन अभी भी वही सब कुछ हो रहा हैं जो बेहद चिंताजनक स्थिति है जिसे किसी भी प्रकार से न तो न्याय के अनुकूल कहा जा सकता है और न ही मानवाधिकार सम्मत। इस रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए राजस्थान सरकार ने जेल के नियमों में बदलाव का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया यह बड़ी बात है, इससे उम्मीद की कोई नई किरण सामने आ सकती है ।21वीं सदी में भी जाति के आधार पर काम कराये जाते हैं। यह संज्ञान में आते ही सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है कि जेलों में जाति के आधार पर काम कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जेल नियमावली के कुछ प्रावधान पढ़ते हुए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड ने उत्तर प्रदेश सरकार के वकीलों को फटकार लगाई जो यह दावा कर रहे थे कि जेलों में जातिगत भेदभाव नहीं होता।

मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि जिस नियम 158 में मैला ढोने के कर्तव्य का ज़िक्र है. यह मैला ढोने का कर्तव्य क्या है? इसमें मैला ढोने वालों की जाति का उल्लेख क्यों है. इसका क्या मतलब है? उत्तर प्रदेश सरकार के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि यूपी की जेलों में कैदियों के साथ कोई जातिगत भेदभाव नहीं होता है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा कर रही है। सुकन्या शांता ने दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में जनहित की इस आशय की याचिका दायर की थी कि जेलों में जातिगत भेदभाव होता है। जहां तक जेलों में बंदियों का प्रश्न है। पहले भी जब राजनीतिक बंदी जाते थे तो उनके लिए कुछ ऐसी जातियों के लोगों को भी बंदी बनाकर बंद करा दिया जाता था जो उन लोगों के काम आ सकें। इनमें नाई, भंगी आदि होते थे। तब शौचालय भी आज के शौचालयों से भिन्न होते थे और मल उठाकर फेंका जाता था। सिर पर मैला ढोना एक प्रथा थी जो न सिर्फजेलों में बल्कि जेल से बाहर भी उसी प्रकार के कार्य होते थे जिस पर रोक लगाई गई और उन्हें दूसरे कामों में पुनर्वासित करने की योजना लायी गई लेकिन जब तक उस प्रकार के शौचालयों का अन्त नहीं हुआ यह काम होता रहा। जेलों में जातिगत भेदभाव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु समेत 17 राज्यों से रिपोर्ट मांगी है और जेल के अंदर जातिगत भेदभाव और जेलों में कैदियों को जाति के आधार पर काम दिए जाने पर जवाब मांगा है ।इससे यही लगता है कि दुनिया बदल गई है सब कुछ बदल गया है लेकिन हम अभी भी वहीं के वहीं लकीर के फकीर बने हुए हैं। परम्परा और मानसिकता के आधार पर वही सब कुछ करते जा रहे हैं जो वर्षो पहले करते आये थे। यही कारण है कि अभी तक सभी राज्यों ने अपनी रिपोर्ट तक नहीं भेजी है। सुप्रीम कोर्ट के पास छः माह में सिर्फउत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने ही अपना जवाब दिया है।

छह पुस्तकों का एक साथ लोकार्पण गौरवपूर्ण : प्रो. पूनम

चिंतन की दुनिया में रचनात्मक हस्तक्षेप हैं लोकार्पित पुस्तकें: प्रो. प्रशांत श्रीवास्तव

गोरखपुर (जीकेबी)। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग और अयोध्या अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में प्राच्य विद्या की छह पुस्तकों का लोकार्पण सोमवार को संवाद भवन में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने कहा कि एक साथ छह पुस्तकों का विमोचन प्राचीन इतिहास विभाग और अयोध्या अध्ययन केंद्र की सक्रियता, चिंतन व उच्च अकादमिक परिवेश का प्रमाण है। इससे प्राचीन इतिहास विभाग के गौरवपूर्ण अतीत का भी पता चलता है। ये पुस्तकें शोध और विमर्श की दिशा में रचनात्मक हस्तक्षेप हैं। अयोध्या अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रो. राजवंत राव ने **'भारतीय अभिलेखों में स्त्री'** पुस्तक पर कहा कि यूरोपीय विद्वानों की ओर से स्त्री के संदर्भ में भारतीय समाज पर गतिहीनता का आरोप उचित नहीं है। प्रो. विपुला दुबे की यह पुस्तक गंभीर चिंतन व शोध का परिणाम है।

मुख्य अतिथि लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध मुद्राशास्त्री प्रो. प्रशांत श्रीवास्तव ने **'भारत का विश्व संस्कृतियों से संवाद'** पर कहा कि संवाद धर्मी संस्कृतियां मरती नहीं, एक-दूसरे से मिलकर समृद्ध होती हैं। भारतीय संस्कृति ने विश्व की संस्कृतियों से निरंतर आदान-प्रदान किया है। उन्होंने प्रो. राजवंत राव की इस पुस्तक को संकीर्णता के खिलाफ संवाद धर्मी भारतीय संस्कृति को रेखांकित करने वाला बताया। **'प्राचीन भारत में कृषि एवं जल संसाधन'** के लेखक 95 वर्षीय प्रो. जयमल राय ने पुस्तक लोकार्पण पर खुशी व्यक्त करते हुए कुलपति प्रो. पूनम टंडन की ओर से विश्वविद्यालय में स्वस्थ अकादमिक वातावरण बनाने के लिए साधुवाद दिया। प्रो. दिवाकर प्रसाद तिवारी की पुस्तक ह्यगोरखपुर परिक्षेत्र का ऐतिहासिक परिदृश्यह्व, डॉ. सुधीर कुमार राय की **पूर्व मध्यकालीन भारत में भू राजस्व नीति एवं कृषक** तथा डॉ. मणिंद्र यादव की **प्राचीन भारत की आर्थिक स्थिति** का भी लोकार्पण हुआ।

स्वागत विभागाध्यक्ष प्रो. प्रज्ञा चतुर्वेदी ने किया। प्रो. दिग्विजयनाथ मौर्य ने आभार व्यक्त किया। डॉ. विनोद कुमार ने संचालन किया। कार्यक्रम में प्रो. चितरंजन मिश्र, प्रो. धीरेंद्र सिंह, प्रो. दिव्या रानी सिंह आदि मौजूद रहे।

यमुना में प्रदूषण जांचने के लिए टीम ने लिया नमूना

इटावा (जीकेबी)। चकरनगर क्षेत्र के बिघौली पुल के नीचे बुधवार को बड़ी संख्या में मृत मछलियां मिलने के मामले की मत्स्य विभाग ने यमुना में प्रदूषण बढ़ने की आशंका जताई थी। शुक्रवार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने चकरनगर क्षेत्र में कई जगह से नमूने लिए हैं।

शुक्रवार को दीपक कुमार, चंबल सेंक्चुअरी के वन दरोगा विष्णु कुमार ने टीम के साथ यमुना के दोनों किनारों पर यमुना के जल का नमूना लिया गया। वहीं, चकरनगर क्षेत्र में भी यमुना के जल का नमूना लेकर प्रयोगशाला भेजा है। टीम ने बताया कि हर साल बारिश के दिनों में ऑक्सीजन की कमी हो जाने से मछलियां मर जाती हैं। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम की जांच में प्रथम दृष्टया को यमुना में कोई भी रासायनिक उत्प्रवाह न होने की बात बताई है। दीपक कुमार ने बताया कि जांच के लिए नमूने आगरा स्थित लैब में भेजे जा रहे हैं। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।

यमुना की मछलियों का सेवन न करें

मत्स्य डीडी गायत्री पांडे ने बताया कि मछलियां मरने का मामला प्रकाश में आया था। इस पर जांच कराई जा रही है। सभी से अपील है कि यमुना में मछलियों का पालन न करें। लोगों से यह भी अपील है कि उसमें पलने वाली मछलियों को खाने से परहेज करें।

एक फिल्म से ट्रेंड सेटर बन गई आरती

80 के दौर में सुपरस्टार अभिनेत्रियां साड़ी और ड्रेस पहनकर मयार्दा में रहती थी वहीं दूसरी तरफ कुछ अभिनेत्रियां ऐसी भी थी जिन्होंने बिकनी और सार्ट ड्रेस पहनकर रात-रात लाइव लाइट में आकर तहलका मचाया हुआ था। भारतीय सिनेमा के वेस्टर्न लुक देने वाली ऐसी अनेक अभिनेत्रियां हैं लेकिन यह किस अभिनेत्री की हम चर्चा करेंगे उसे अभिनेत्री ने सिनेमा जगत में एक ही फिल्म के साथ ट्रेडमार्क सेट कर दिया। भारत की एक मंत्र सबसे डरावनी माने जाने वाली फिल्म पुराना मंदिर देखो संघ प्रदर्शन करने वाली अभिनेत्री आरती गुप्ता को आज भी किसी ने बुलाया नहीं होगा ।यह आरती गुप्ता महान गायक सुरेंद्रनाथ की बहू है। वही सुरेंद्रनाथ जिन्होंने बताओ रविकता एक से बढ़कर एक फिल्मों में अभिनय किया था। 40 और 50 के दशक में सुरेंद्रनाथ का सिक्का खूब चलता था आगे चलकर उनके बेटे कैलाश सुरेंद्र नाथ ने मात्र 18 वर्ष की उम्र में विज्ञापन के क्षेत्र में कदम रखा और 1980 के दौर से लेकर आज तक वह सेवाएं अपनी प्रदान कर रहे हैं। कैलाश सुरेंद्रनाथ का नाम उल्लेख किया जाना इसलिए भी आवश्यक है कि

आवश्यक है कि इन्होंने ही आरती गुप्ता के करियर को बनाया था इतना ही नहीं सलमान खान को भी विज्ञापन के क्षेत्र में लाने का क्रेडिट भी कैलाश और आरती गुप्ता को ही जाता है। 1983 में कैंपर कला विज्ञापन रिलीज हुआ था जिसमें आरती गुप्ता के साथ सलमान खान पहली बार दिखाई दिए थे। आरती गुप्ता ने 1980 में मॉडलिंग करना शुरू किया था उसके बाद 1981 में उसकी पहली फिल्म तजुर्बा रिलीज हुई इस फिल्म में उन्होंने राज बब्बर की प्रेमिका की भूमिका निभाई थी। उसके बाद कुछ कम बजट वाली फिल्मों में झलकने के बाद उनकी पहचान कैलाश से हुई। कैलाश ने उन्हें विज्ञापन उतारा और कृपा कला के बहाने आरती गुप्ता लोकप्रिय होने लगी इसके बाद रिलीज हुई उनकी पुराना मंदिर फिर उन्हें सिनेमाघर में तहलका मचाया फिल्म का भूत संगीत कथा और फिर नामांकन के अलावा आर्थिक गुप्ता के इंटीमेट सीन में भी लोगों के ख्यालों को जलाकर रख दिया। यहां पर यह भी जन्म आवश्यक हो जाता है कि उन जैसे कोई स्टार अभिनेत्री नहीं आई है जिसे ऐसी सेन के कारण सुपरस्टार का दर्जा मिला हो। इस वजह से बड़े-बड़े फिल्म करो ने आरती गुप्ता को अपनी फिल्म कष्ट करना जरूरी नहीं समझा था किंतु यह भी सच है की आरती गुप्ता ने पुराना मंदिर जैसे कुछ और फिल्मों में आगे भी काम किया लेकिन पुराना मंदिर की सफलता के आगे कोई भी फिल्म चल नहीं पाई। दुर्भाग्य दिवस आगामी 5 वर्षों के भीतर आरती गुप्ता का स्तर पूरी तरह से डर हुआ गया गिर गया लेकिन यहां पर यह समझना जरूरी है कि आर्थिक गुप्ता विज्ञापन के क्षेत्र में आज भी राज कर रही है

1985 में कैलाश से शादी करने के बाद आरती गुप्ता ने खुद को फिल्मों से दूर करने की कोशिश की लेकिन आराम से ब्रदर्स के बार-बार समझाने के बाद उन्होंने कुछ हॉरर फिल्में साइन कर ली। उसके बाद महेश भट्ट की आशियाना फिल्म में भी उन्होंने एक किरदार निभाया था साथ ही टीवी शहर वाहिकों के लिए कुछ पल बिताए लेकिन इतना सब करने के बाद भी उनके करियर को उड़ान नहीं मिली और आखिरकार 90 के दशक के बाद आरती गुप्ता ने विज्ञापनों की दुनिया से नाता जोड़ लिया।

इन दिनों वह अपने पति की विज्ञापन एजेंसी में सक्रिय है उनके करियर को लेकर यह भी कहा जा सकता है कि 90 के दशक में शाहरुख खान और गौरी खान ने किसी विज्ञापन के लिए एक साथ अभिनय भी किया था।

अब आरती गुप्ता के मुख्य प्राथमिक जीवन पर भी चर्चा थोड़ी बहुत कर ली जाए उनका जीवन 1964 में मुंबई में ही शुरू हुआ उनके पिता मेजर ज्ञान गुप्ता इंडियन आर्मी के बड़े अफसर थे और उसे दौरान फिल्म कारों को शूटिंग के लिए हथियार और आर्मी के टैन्क्स उपलब्ध कराते थे इस वजह से बहुत सारे नवी फिल्मकारों को उनके घर का रास्ता मालूम था और वह आते जाते रहते थे आगे चलकर सनसिल्क शैंपू के विज्ञापन के लिए 15 साल की आर्थिक गुप्ता का सिलेक्शन हुआ उसके बाद मुंबई टाइम जैसी अनेक कंपनियों में उन्होंने काम किया।

आदित्य धर के साथ रणवीर सिंह की फिल्म का आधिकारिक घोषणा

27 जुलाई को बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह ने आदित्य धर के साथ अपनी अगली बड़ी फिल्म की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने फिल्म के मुख्य कलाकारों का भी खुलासा किया है, जिसमें बॉलीवुड के कई धुरंधर अभिनेता अपनी अधिकारी का दम दिखाएंगे। हालांकि, उन्होंने फिल्म के शीर्षक का खुलासा नहीं किया है।

इस अनाम फिल्म में संजय दत्त, आर. माधवन, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल जैसे स्टार कलाकार हैं। यह बड़ी फिल्म जियो स्टूडियो और बी62 स्टूडियो द्वारा निर्मित है।

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म 'उरीः द सर्जिकल स्ट्राइक' के लिए मशहूर निर्देशक आदित्य धर अपनी दूसरी बड़ी मोशन पिक्चर का निर्देशन करने के लिए तैयार हैं, जिसमें प्रभावशाली कलाकारों की टुकड़ी के साथ एक रोमांचक ड्रामा होने का वादा किया गया है।

निमार्ताओं ने आधिकारिक तौर पर फिल्म के शीर्षक की घोषणा नहीं की है, लेकिन फिल्म का अस्थायी शीर्षक 'धुरंधर' रखा गया है।

निर्देशक के साथ सभी अभिनेताओं की तस्वीरों का एक कोलाज साझा करते हुए रणवीर ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'यह मेरे प्रशंसकों के लिए है, जो मेरे साथ बहुत धैर्य रखते हैं और इस तरह के मोड़ के लिए चिल्ला रहे हैं।

मैं आप सभी से प्यार करता हूं और मैं आपसे वादा करता हूं इस बार एक ऐसा सिनेमाई अनुभव जैसा पहले कभी नहीं हुआ।

आपके आशीर्वाद के साथ हम उत्साही ऊर्जा और शुद्ध इरादे के साथ इस महान, बड़े मोशन पिक्चर एडवेंचर पर निकल पड़े हैं। इस बार यह व्यक्तिगत है।'

जब अभिनेता मनोज कुमार ने भारत सरकार के खिलाफ कोर्ट केस जीता

भारतीय सिनेमा के इतिहास में कई अभिनेता आए और गायब हो गए लेकिन कोई भी महान अभिनेता मनोज कुमार जैसा नहीं था। दिग्गज अभिनेता जिन्होंने हिंदी सिनेमा को कई रत्न दिए और हमेशा अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। मनोज ने पर्दे पर कई बेहतरीन किरदार निभाए। अपनी फिल्मों के जरिए मनोज कुमार ने लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई और वे देशभक्ति वाली फिल्में बनाने वाले पहले बॉलीवुड अभिनेता बन गए। मनोज कुमार आज अपना 87वां जन्मदिन मना रहे हैं।

दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता के साहसी रवैये के कई किस्से हैं, जिनमें से एक हम आपके लिए लेकर आए हैं। यह किस्सा मनोज कुमार और इंदिरा गांधी के बीच हुए विवाद का है जब आपातकाल की घोषणा के बाद दोनों आमने-सामने खड़े थे।

> भारतीय सिनेमा के इतिहास में कई अभिनेता आए और गायब हो गए लेकिन कोई भी महान अभिनेता मनोज कुमार जैसा नहीं था। दिग्गज अभिनेता जिन्होंने हिंदी सिनेमा को कई रत्न दिए और हमेशा अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे।

आपातकाल के बाद मनोज का गुस्सा

जैसा कि हम देखते हैं, शुरूआती दौर में मनोज कुमार और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही आपातकाल की घोषणा हुई, दोनों के बीच काफी कुछ बदल गया। कुमार ने आपातकाल का खुलकर विरोध किया। कहा जाता है कि आपातकाल का विरोध करने वाले फिल्मी सितारों पर इस कदर प्रतिबंध लगाया गया कि उनकी फिल्म भी रिलीज होते ही बैन हो गई। मनोज कुमार की फिल्म 'दस नंबरी' के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बैन कर दिया था और इसके बाद रिलीज हुई फिल्म 'शोर' का भी यही हाल हुआ।

'शोर' के निर्देशक और निमार्ता मनोज ही थे। इस फिल्म को रिलीज होने से पहले ही दूरदर्शन पर दिखाया गया, जिसकी वजह से फिल्म सिनेमाघरों में कमाई नहीं कर पाई और भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके बाद फिल्म पर भी बैन लगा दिया गया।

मनोज ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

ऐसी स्थिति में मनोज कुमार के पास कोई विकल्प नहीं बचा और उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कई हफ्तों तक कोर्ट के चक्कर लगाए, लेकिन इससे उन्हें फायदा हुआ और फैसला उनके पक्ष में आया। इसकी वजह से वे एकमात्र ऐसे फिल्म निमार्ता हैं, जिन्होंने भारत सरकार के खिलाफ केस जीता है। इस केस के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने उन्हें 'आपातकाल' पर फिल्म बनाने का ऑफर दिया, लेकिन मनोज ने इसे ठुकरा दिया और साफ मना कर दिया। अमृता प्रीतम इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रही थीं और यह एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म होने वाली थी। जब मनोज को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अमृता प्रीतम को खूब डांटा। बाद में यह फिल्म कभी नहीं बन पाई।

'मुझे देखकर डॉक्टर घबरा गए थे' : जान्हवी कपूर

अभिनेत्री जान्हवी कपूर को 18 जुलाई को फूड पॉइजनिंग के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुछ दिनों में उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। हाल ही में, अभिनेत्री ने अपने स्वास्थ्य के बारे में एक अपडेट साझा किया और बताया कि यह पहली बार था जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह पाचन प्रतिरक्षा विकार से पीड़ित थीं। एक साक्षात्कार के दौरान जान्हवी ने बताया कि कैसे उनका शरीर थका हुआ था क्योंकि वह अपनी फिल्म 'मिस्टर एंड मिसेज माही' के प्रचार शुरू करने से पहले ही लगातार काम कर रही थीं। एक महीने के भीतर, उन्होंने बिना ब्रेक लिए तीन गाने शूट किए और चौथे गाने के लिए रिहर्सल कर रही थीं। इस बीच, वह यात्रा भी कर रही थीं और कार्यक्रमों में भी भाग ले रही थीं। जान्हवी ने कहा, मैंने वास्तव में कोई ब्रेक नहीं लिया है। जब उनके शरीर की प्रतिरक्षा कमजोर हो रही थी, तब जान्हवी एक कार्यक्रम के लिए चेन्नई गई थीं और हवाई अड्डे पर कुछ फंकी खाया था। जान्हवी ने बताया, शुरू में हमें लगा कि यह पेट में कीड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि जब उन्होंने ये सभी टेस्ट किए तो मेरे सभी ब्लड पैरामीटर्स में गड़बड़ी थी। और जब मेरा पेट ठीक हो गया तो मुझे बस शरीर में दर्द, कमजोरी, कंपकंपी और हिलना-डुलना जैसी कई तरह की परेशानियाँ थीं। सिर्फ.पेट ही नहीं, जान्हवी के लिवर टेस्ट ने भी उनके डॉक्टरों को डरा दिया था। 'धड़क' की अभिनेत्री ने बताया, मेरे लिवर एंजाइम और लिवर प्रोफाइल में बहुत गड़बड़ी थी, जिससे डॉक्टरों को बहुत घबराहट हुई। उन्होंने आगे बताया, इसलिए तीन-चार दिनों तक मैं अस्पताल में ही थी और वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे क्या परेशानी है और मेरे पैरामीटर इतने गड़बड़ क्यों हैं। जान्हवी कपूर ने कहा कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति काफी डरावनी थी। फिर भी, उन्हें बस अपने डांस की चिंता थी और उन्हें इस बात की चिंता थी कि क्या वह काफी फिट दिख रही हैं ताकि वे अच्छा डांस कर सकें। अभिनेत्री ने यह भी याद किया कि कैसे, जब वह हैदराबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट पकड़ने वाली थीं, तो उन्हें पूरी तरह से विकलांग और लकवाग्रस्त महसूस हुआ। वह खुद से वॉशरूम भी नहीं जा पाती थी और सोने, चलने या खाने में असमर्थ थी। स्वास्थ्य संबंधी डर का अनुभव करने के बाद, जान्हवी ने सीखा है कि किसी को अपने शरीर का ₹सम्मान₹ करना चाहिए और उसकी सुनना चाहिए। अब, एक्ट्रेस ने काम फिर से शुरू कर दिया है, लेकिन वह अभी भी काफी कमजोर महसूस करती है।

पायल मलिक ने अपने ट्रोलर्स के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया

बिग बॉस ओटीटी 3 की पूर्व प्रतियोगी और यूट्यूबर अरमान मलिक की पहली पत्नी पायल मलिक ने उन्हें धमकी देने वालों के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है। हाल ही में इंस्टाग्राम पर पायल ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने ट्रोल किए जाने और परेशान किए जाने के बारे में बात की।

बिग बॉस ओटीटी 3 की पूर्व प्रतियोगी और यूट्यूबर अरमान मलिक की पहली पत्नी पायल मलिक ने उन्हें धमकी देने वालों के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है। हाल ही में इंस्टाग्राम पर पायल ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने ट्रोल किए जाने और परेशान किए जाने के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि उन्होंने कानूनी कार्रवाई की है और जल्द ही उन्हें बदनाम करने वालों को नोटिस भेजा जाएगा। उन्होंने कहा, अभी तक ट्रोलिंग चल रही थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई इंसान बढ़ता है तो उसे ट्रोलिंग सबसे पहले मिलती है। पैड अब जो है ना मुझे बहुत सारी धमकियां आ रही है (अब तक, मुझे ट्रोल किया जा रहा था, मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। जब कोई व्यक्ति महान ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, तो उसे ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब, मुझे बहुत सारी धमकियां मिल रही हैं)। पायल ने कानूनी कार्रवाई की पायल ने आगे कहा, ₹जो लोग भी ये कर रहे हैं ना, जो मुझे बदनाम कर रहे हैं या मेरे परिवार को बदनाम कर रहे हैं उनके लिए मैं सीधा मान हानि का केस डालने आई हूं।₹ पायल ने यह भी कहा, ₹अब जो भी होगा, आकर खुद भुगतना पड़ेगा क्योंकि आप ही लोग कर रहे हैं ये सब। मैंने यहां पर नाम दिया है। जिसका नाम दिया है उनको नोटिस बहुत जल्दी मिलने वाला है। उन्होंने हाथ जोड़ने वाले इमोजी के साथ वीडियो पोस्ट किया।

पायल के परिवार के बारे में

उन्हें शो से जल्दी ही निकाल दिया गया था, जबकि अरमान और उनकी दूसरी पत्नी कृतिका मलिक फिलहाल बिग बॉस ओटीटी 3 के घर में हैं।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकज धर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45, बादशाह बाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर से प्रकाशित।
संपादकः पंकज धर द्विवेदी
संपर्क सूत्र : ghoonghatkibagawat37@gmail.com